नई दिल्ली
10 जुलाई, 2026 शुक्रवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 99

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

बाबर आजम को फिर से टी20 कप्तान बना सकता है पीसीबी 07

संक्षिप्त वार्ता

फ्लाईओवर पर स्कूल वैन हादसे का शिकार

भोपाल, वेब वार्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। पंचवटी क्षेत्र से बच्चों को लेकर जा रही भोपाल गर्ल्स स्कूल की वैन कोहेफिजा थाने के सामने फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार छह बच्चे सुरक्षित बच गए, जबकि आगे की सीट पर बैठी स्कूल की एक महिला स्टाफ सदस्य घायल हो गई। उनके सिर में चोट आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गर्ल्स हॉस्टल में घुसा जहरीला करैत सांप, सो रही 4 छात्राओं को डसा

वेब वार्ता, लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र स्थित रोचो माहुआटोली के सनवासिरा हायर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में आधी रात को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छात्राओं के कमरे में एक अत्यधिक जहरीला करैत सांप घुस गया और उसने बिस्तर पर सो रही चार छात्राओं को अपना शिकार बना लिया। सर्पदंश के कारण 13 वर्षीय एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चियों की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे के बाद से हॉस्टल और परिजनों में कोहराम मच गया है।

सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी, मौत

वेब वार्ता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार को हुई। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश निवासी वाई. चंद्रा रेड्डी के रूप में हुई है। वह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन की एफ कंपनी में तैनात थे। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

अधिकारियों ने बताया कि जवान ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। साथ ही उसके सहकर्मियों और संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

ईरान ने अंतिम संस्कार से पहले जारी किया दिवंगत खामेनेई के तबाह घर का वीडियो

तेहरान। ईरान सरकार ने बुधवार देर रात पहली बार दिवंगत सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के आवासीय परिसर पर हुए हमले और उससे हुई तबाही का वीडियो जारी किया है। वीडियो 35 सेकेंड का है। यह ऐसे समय आया है, जब तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। बता दें खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मृत्यु हो गई थी। हमले में उनके परिवार के कई सदस्यों और 40 अफसरों की जान भी गई थी। इसमें खामेनेई की 14 महीने की पोती भी शामिल थी। अमेरिका-इजराइल ने एक साथ 35 मिसाइलें घर पर गिराई थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के घर का नाम ह्यबैत-ए-रहबरीह्न था। यह अत्यधिक सुरक्षित सरकारी परिसर था, जो तेहरान के बीच में स्थित था। यही उनका आधिकारिक आवास, कार्यालय और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। बाहर से यह परिसर अपेक्षाकृत सादा दिखता था। इसमें भव्य महलों जैसी सजावट नहीं थी। यह परिसर के अंदर एक बड़ा सभा हॉल था, जहां खामेनेई धार्मिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विदेशी प्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात करते थे। भाषण देते थे। हाल में जारी वीडियो में इसी हॉल को भारी नुकसान हुआ दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह केवल एक मकान नहीं था, बल्कि इसमें कार्यालय, बैठक कक्ष, सुरक्षा सुविधाएं, आवासीय हिस्से और प्रशासनिक भवन शामिल थे।

बाबा बफानी हुए अंतर्ध्यान

फिर भी 10 हजार श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

वेब वार्ता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए भगवती नगर यात्री निवास से अब तक का सबसे बड़ा एकदिवसीय जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 9,837 श्रद्धालुओं का सातवां जत्था 361 वाहनों के काफिले के साथ कश्मीर के पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों के लिए रवाना किया गया। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

जानकारी के अनुसार, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से 188 वाहनों में 5,337 श्रद्धालुओं को भेजा गया, जबकि छोटे बालटाल मार्ग से 173 वाहनों में 4,500 श्रद्धालु रवाना हुए। इस जत्थे में 6,684 पुरुष, 2,730 महिलाएं, 21 बच्चे, 320 साधु, 80 साध्वियां तथा दो ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से भगवती नगर यात्री निवास परिसर में सुबह से ही धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं में बाबा बफानी के पवित्र दर्शन को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। यात्रा पर निकलने से पहले श्रद्धालुओं ने सुरक्षा जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन, भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।

यात्रा मार्ग पर पुलिस, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगातार तैनात हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उल्लेखनीय है कि 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है। यह धार्मिक यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ संपन्न होगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बफानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे।

ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित

राष्ट्रगान से गूंजा मेलबर्न, पीएम एंथनी ने किया गर्मजोशी से स्वागत

वेब वार्ता, मेलबर्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भव्य तरीके से औपचारिक स्वागत किया गया। गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया में आयोजित समारोह में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस दौरान भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गूंजा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी ने उन्हें औपचारिक सलामी दी।

औपचारिक स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि स्कॉट मॉरिसन से मिलना हमेशा सुखद रहता है और दोनों नेताओं के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया मित्रता को और मजबूत बनाने पर सार्थक चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में संयुक्त रूप से भाग लिया। दोनों नेताओं ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को नई गति देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने फोरम में दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए भारत में निवेश के बढ़ते अवसरों की जानकारी दी।

अखिलेश ने शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद

वेब वार्ता, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गुरुवार सुबह लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। यह 30 मिनट की मुलाकात, जिसमें अखिलेश जमीन पर बैठे दिखाई दिए, चार माह में दोनों नेताओं की दूसरी बैठक थी। इस भेंट के बाद अखिलेश यादव ने बताया कि शंकराचार्य गौमाता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने को लेकर बेहद चिंतित हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं, शंकराचार्य ने मंदिर में हुए कथित घोटाले पर खुलकर बात की, मुख्यमंत्री पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर इतना तक कह दिया कि जब नया मुख्यमंत्री आएगा, तब तगड़ी कार्रवाई करेगा। शंकराचार्य, जो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 81 दिवसीय गोरक्षार्थ-धर्मयुद्ध यात्रा पर हैं, ने अखिलेश से हुई बातचीत में कहा कि भले ही लोग गाय को माता मानते हों, लेकिन सरकार गाय को पशु मानती है। सपा प्रमुख अखिलेश ने शंकराचार्य के आरोपों का समर्थन कर राम मंदिर चढ़ावे की चोरी को महापाप बताया और सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा, कहते हुए कि इन्होंने ही यह महापाप किया है। उन्होंने दावा किया कि मामले के सामने आने के बाद भाजपा में भगदड़ मच गई है और बहुत से लोग अभी से उनसे संपर्क साध रहे हैं, जबकि मौजूदा एसआईटी जांच को उन्होंने लीपापोती करार दिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई नाना पटवारी गिरफ्तार

वेब वार्ता, इन्दौर। एक सनसनीखेज घटनाक्रम के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने नाना पटवारी को सनसाईन फॉर्म हाउस से पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नाना पटवारी को ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई कर देर रात पकड़ाएं दो ड्रग्स पैडलरों की गिरफ्तारी के बाद उनसे की गई पूछताछ के आधार पर की। पूछताछ के दौरान नाना पटवारी का नाम सामने आया जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। वहीं यह बात भी सामने आई है कि नाना ने भी आरोपितों को जानने की बात स्वीकार की है। जिसके बाद पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उनसे नाना का संबंध केवल परिचय तक सीमित था या ड्रग्स नेटवर्क से कोई अन्य कड़ी भी जुड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी पर पहले भी कई केस गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। नवंबर 2018 में एक केस उन पर महिला संबंधी अपराध में धारा 354 (क) में दर्ज हुआ था। जिसमें महिला ने नाना पर आरोप लगाए थे कि नाना के साथ क्रुणाल पटवारी, चेतन, सुदील चौधरी, चेतन पटवारी, गब्बू पटवारी व अन्य कार, बाइक से मेरे घर के अंदर घुस आए थे। नाना के हाथ में पिस्टल थी, बाकी के हाथ में चाकू और तलवार थी। नाना पटवारी ने मेरा हाथ बुरी नीयत से पकड़ा था। वहीं नाना पर 2018 विधानसभा चुनाव में पोलिंग वाले दिन यूवा मोर्चा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष अंकित परमार के घर पर हमला करने के आरोप भी लगे थे।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में युवाओं से करेंगे संवाद

वेब वार्ता, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत शहर के युवाओं से बातचीत करने 17 जुलाई को देहरादून जाएंगे। यह दौरा राजस्थान के कोटा में पहले हुए ह्यछात्रों की गूंजह्न प्रोग्राम के मॉडल पर आधारित होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी के मुताबिक राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में युवाओं से मिलेंगे, उन्होंने इस कार्यक्रम की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने पिछली बार 4 जून को उत्तराखंड का दौरा किया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अल्मोड़ा में उनकी जनसभा और पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ तय बातचीत को टालना पड़ा था। छात्रों की गूंज अभियान का मकसद छात्रों की समस्याओं को सामने लाना है, जिनमें परीक्षा में गड़बड़ियां और भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बड़ी चुनौतियां शामिल हैं। राहुल ने सबसे पहले कोटा में छात्रों की गूंज महारैली के जरिए इस अभियान की शुरूआत की थी और अब देहरादून के दौरे के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को प्रभावित करने वाले मानसिक स्वास्थ्य संकट और व्यवस्थागत बाधाओं से निपटने के लिए संवाद एक अहम कदम है।

भोपाल में एथेनॉल से भरे टैंकर के केबिन में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला

टैंकर का केबिन जलकर खाक

भोपाल, वेब वार्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। आयशर कॉलेज के पास एथेनॉल से भरे एक टैंकर के केबिन में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग टैंकर के पिछले हिस्से तक नहीं पहुंची, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दमकल विभाग की मुस्तैदी से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे की है। आयशर कॉलेज के पास सड़क किनारे खड़े या गुजर रहे एक टैंकर के केबिन से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। संबंधित डिपो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टैंकर के पिछले हिस्से (कंटेनर) में एथेनॉल भरा हुआ था। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल मोर्चा संभाला और महज एक ही फायर ब्रिगेड वाहन की मदद से पानी की बौछारें कर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने आग को केबिन तक ही सीमित रखा और उसे पीछे एथेनॉल वाले मुख्य टैंक तक फैलने नहीं दिया। यदि आग टैंक तक पहुंच जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस घटना में ट्रक का पूरा केबिन जलकर खाक हो गया।

दमकल विभाग और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केबिन में आग किन कारणों से लगी, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। शुरूआती जांच में इसे अज्ञात शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हादसे के समय और आग बुझने के बाद भी ट्रक का चालक मौके पर नहीं मिला। ऐसे में आग कैसे लगी और चालक कहां गया, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। घटना के दौरान सड़क पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। अधिकारियों का कहना है कि ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है, लेकिन एथेनॉल सुरक्षित है और कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस लापता ड्राइवर की तलाश करने और आग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है।

मणिपुर में नगा-कुकी संघर्ष ने बढ़ाई चिंता, पांच माह में 25 की मौत

असम राइफल्स पर हमले में शहीद जवानों को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित

वेब वार्ता, इम्फाल। मणिपुर में मई 2023 से जारी मैतेई-कुकी जातीय हिंसा के बीच अब नगा और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के उखरुल और आसपास के क्षेत्रों में इस वर्ष फरवरी से शुरू हुए ताजा संघर्ष में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। हाल के महीनों में हिंसा की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे राज्य में शांति बहाली की कोशिशों को झटका लगा है।

इस तनाव का असर सुरक्षा बलों पर भी पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को भारत-म्यांमार सीमा की निगरानी कर रहे असम राइफल्स के एक काफिले पर हमला किया गया, जिसमें उत्तराखंड के दो

जवान शहीद हो गए। गुरुवार को इंफाल हवाई अड्डे पर दोनों शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद दोनों जवानों के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भेज दिए गए।

नगा समुदाय ने असम राइफल्स पर भारत-म्यांमार की लगभग 398 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रभावी निगरानी नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीमा पार से सक्रिय सशस्त्र संगठन कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा) के सदस्य म्यांमार से भारतीय सीमा में प्रवेश कर नगा बहुल गांवों पर हमले कर रहे हैं। नगा संगठनों का आरोप है कि सुरक्षा बलों का रवैया कुकी समुदाय के प्रति अपेक्षाकृत नरम रहा है, जिससे सीमा पार गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। नगा समुदाय में नाराजगी उस समय और बढ़ गई जब 10 जून को छह अगवा किए गए नगा लोगों के क्षत-विक्षत शव बरामद हुए।

देश में हर दिन औसतन 13 स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक असर

यूडाइस प्लस की रिपोर्ट से हुए खुलासे से शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

वेब वार्ता, नई दिल्ली

देश में स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है। शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस प्लस (यूडीआईएसई+) 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बीते एक वर्ष में देशभर में 4,791 स्कूल बंद हो गए, यानी औसतन हर दिन 13 स्कूलों का संचालन बंद हो गया। वर्ष 2024-25 में देश में कुल 14,71,473 स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 14,66,682 रह गए। सबसे अधिक 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए, जबकि तेलंगाना में 1,392, पश्चिम बंगाल में 568, आंध्र प्रदेश में 474, तमिलनाडु में 369, कर्नाटक में 281 और हिमाचल प्रदेश में 266 स्कूल बंद हुए। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है, कि कई राज्यों में छोटे स्कूलों का बड़े विद्यालयों में विलय किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ राज्यों में नए स्कूल खुले हैं, लेकिन वहां भी छात्रों के नामांकन में गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। बिहार में 946 नए स्कूल जुड़े, इसके बावजूद छात्र नामांकन में 4.37 लाख की कमी दर्ज की गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 234 और दिल्ली में 87 नए स्कूल बढ़े, लेकिन दोनों राज्यों में भी नामांकन घटा है।

बिना एनरोलमेंट वाले स्कूल घटे

ताजा रिपोर्ट में यह भी सामने आया, कि देश में पहली बार जीरो एनरोलमेंट यानी बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या घटी है। ऐसे स्कूलों की संख्या 7,993 से घटकर 5,663 रह गई है। हालांकि इन स्कूलों में अब भी 20,667 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं।

इन राज्यों में बिना छात्र वाले स्कूलों की संख्या बढ़ी

पश्चिम बंगाल में स्थिति इसके विपरीत है। वहां बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 4,133 हो गई है, जिनमें 19,502 शिक्षक तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे स्कूल 81 से बढ़कर 313 हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पहली बार 149 जीरो एनरोलमेंट स्कूल दर्ज किए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर घटकर 1,00,843 रह गई है, जो पिछले वर्ष 1,04,125 थी। हालांकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ी है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना या घटाना समाधान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों की नियुक्ति छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुरूप हो। जिन विद्यालयों में छात्र नहीं हैं, वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण उन स्कूलों में किया जाना चाहिए जहां शिक्षकों की कमी है। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी और संतुलित बन सकेगी।

संपादकीय

जांच रपट के अर्द्ध सत्य

राम मंदिर चंदा-चढ़ावा चोरी की कथित जांच कर रहे विशेष जांच दल की परम गोपनीय रपट सार्वजनिक हो गई। रपट पर साफ अक्षरों में लिखा है-परम गोपनीय। फिर यह अंतिम रपट राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासियों के पास कैसे पहुंची? वहां से कई टीवी चैनलों को रपट कैसे मिली? यकीनन यह कानून अपराध का मामला है। रपट को उप्र सरकार सार्वजनिक करती या ट्रस्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति देती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। परम गोपनीय रपट को चोर दरवाजे से सार्वजनिक किया गया, लिहाजा खुलासा हो गया कि विशेष जांच दल ने शुरुआती जांच में क्या पकड़ा, किन्हें काली भेड़ करार दिया गया और यह चोरी-डकैती कांड कैसे अंजाम दिया गया? ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों से ही राम मंदिर के भीतर के चोरी-डकैती कांड का पटाक्षेप नहीं हुआ है। विशेष जांच दल की सार्वजनिक रपट पर ही कई सवाल हैं। रपट में चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देव, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव आदि का उल्लेख क्यों नहीं है? चंपत राय तो प्रमुख खलनायक के तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर से ही, उनके ड्राइवर टिन्नू यादव को, हुंडियों की चाबियां दी गई! टिन्नू को कोई प्राधिकार ट्रस्ट ने नहीं दिया था, फिर वह एक सक्षम अधिकारी की तरह व्यवहार क्यों करता रहा? हालांकि विशेष जांच दल अभी टिन्नू यादव की और जांच-पड़ताल करेगा। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल के भीतर है। सवाल यह भी है कि ट्रस्ट ने राम मंदिर के व्यवस्थापक रहे गोपाल राव को अचानक बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? चंपत और अनिल पर लगे गंभीर आरोप उन पर नहीं थे। वह भी राम मंदिर की व्यवस्था में आरएसएस के एक प्रमुख चेहरा थे।

वह ट्रस्ट की बैठक से पहले अचानक बेंगलुरु गए और संघ के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबाले से मिले। क्यों मिले, इसका कोई खुलासा नहीं है। विशेष जांच दल ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जो कागजात मांगे थे, वे जांच दल को सौंपे गए, लेकिन अंतरिम रपट में घोटालासह भूमि-सौदों का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। क्या जांच दल ने मान लिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने बिल्कुल ईमानदार जमीन-सौदे किए थे? इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने यह तथ्य बेनकाब किया था कि अनिल मिश्रा निर्माण-कार्यों पर 40 फीसदी कमीशन मांगते थे, लिहाजा फर्जी बिल भी बनाए गए। महिपाल सिंह भी राम मंदिर में लेखाधिकारी थे, जिन्होंने चोरी और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा को अवगत कराया था। उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। विशेष जांच दल ने इन दोनों के बयान भी दर्ज क्यों नहीं किए? वे चोरी-डकैती के सुराग खोलने में एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकते थे। सार्वजनिक रपट में खुलासा है कि बीती 5 जून की छापेमारी में 78.94 लाख रुपए बरामद किए गए थे। यह नकदी बरामदगी 21 दिन तक कृष्ण मोहन के घर एक संदूक में रखी गई। कृष्ण मोहन को अब ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है। क्या कोई व्यक्ति बरामदगी को अपने पास रख सकता है? यकीनन ये अपराध का मामला है, लेकिन जांच दल ने इस दृष्टि से आकलन नहीं किया। रपट से ऐसा नहीं लगता कि चोरी-डकैती कांड में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था। इसी बीच चंपत राय का राम-भक्तों के नाम एक पत्र भी सार्वजनिक हुआ है, जिसमें उन्होंने अनिल मिश्रा और भारतीय स्टेट बैंक के बीच करार को अवैध करार दिया है। उनका कहना है कि इस करार की सम्यक जानकारी उन्हें नहीं दी गई और करार पर महासचिव के नाते उनके दस्तखत होने चाहिए थे। अब चंपत अनिल मिश्रा और बैंक को खलनायक बनाने के मूड में लगते हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि विशेष जांच दल की अंतिम रपट के बाद ही वह अपना पक्ष रखेंगे। रपट से साफ है कि चंपत राय और गोविंद देव के खिलाफ किसी भी तरह का केस बनाए जाने के आसार नहीं हैं और प्राथमिकी तो अभी तक दर्ज नहीं की गई है। अभी जांच दल को उन 113 करोड़ रुपए के हिसाब की भी जांच करनी है, जो प्राण-प्रतिष्ठा के मद्देनजर खर्च कर दिए गए। यह कोई सामान्य खर्च नहीं है। इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है और इसमें जो दोषी पाया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा जांच का कोई लाभ नहीं मिलेगा और विपक्ष को एनडीए सरकार पर हमले का मौका मिल जाएगा। योगी सरकार बार-बार दावे कर रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन व्यवहार में भी यह झलक मिलनी चाहिए।

भारत के आर्थिक विकास को रोकने के लिए अमेरिका सब कुछ करेगा

प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी लैंडाऊ के बयान का लहजा कई व्यापार विशेषज्ञों की उन आशंकाओं को सही ठहराता है कि अमेरिका जल्दबाजी में भारत पर ऐसा व्यापार समझौता थोप रहा है जिसमें सिर्फ अमेरिका के हितों की रक्षा हो रही है, भारत के नहीं। ट्रंप-मोदी की दोस्ती और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता जारी रहने के बीच, पूर्व भारतीय गुप्तचर विभाग के प्रमुख विक्रम सूद ने रविवार को एक ब्रिटिश नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाऊ ने मार्च 2026 में अपने भारत दौरे के दौरान भारतीय अधिकारियों से कहा था कि वाशिंगटन भारत की तेज आर्थिक विकास को रोकने के लिए टैरिफ, प्रतिबंध और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करेगा और भारत को अमेरिका के साथ मुकाबला करने वाली एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने नहीं देगा।

सूद के मुताबिक लैंडाऊ ने उस नई दिल्ली बैठक में कहा था, 'हमने चीन को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने में मदद करके गलती की। हम भारत के साथ ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। हम वह गलती दोबारा नहीं करेंगे।' सूद ने यह साक्षात्कार ब्रिटिश करेंट अफेयर्स प्रोग्राम न्यू ऑर्डर में दिया था, जिसे होस्ट ने लैंडाऊ की टिप्पणी के मूल वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस साक्षात्कार ने राजनयिक हल्कों में हंगामा मचा दिया है। लैंडाऊ अभी भी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और उन्हें ट्रंप की मगा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) लॉबी के साथ-साथ अपने बॉस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो के भी करीब माना जाता है। जहां तक भारत-अमेरिकी रिश्तों की बात है, रुबियो सबसे ज्यादा दिखने वाले अमेरिकी अधिकारी हैं, लेकिन लैंडाऊ ट्रंप प्रशासन के मन की बात कहते हैं। वह द्विपक्षीय रिश्तों के भविष्य के बारे में अमेरिकी सोच के बारे में खुलकर बात करते हैं। हाल के दिनों में, ट्रंप प्रशासन भारत सहित भारत-प्रशांत सुरक्षा के अपने पुराने विचार में कम दिलचस्पी ले रहा है। ट्रंप प्रशासन की बड़ी एशिया रणनीति में भारत की अहमियत कम हो गई है। यह सब इस साल मई में बीजिंग में ट्रंप-शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन के बाद हुआ है। नतीजतन, अब उसका ध्यान भारत से व्यापार और रक्षा खरीद में ज्यादा से ज्यादा छूट लेने पर है, और साथ ही यह पक्का करना है कि भारत के विकास की रफ्तार अमेरिकी आर्थिक शक्ति के लिए कोई खतरा न बने।

भारतीय विदेश मंत्रालय भी अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडाऊ की टिप्पणी के असली मतलब का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी क्योंकि लैंडाऊ ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका अब भारत के मामले में ऐसी गलती नहीं करेगा। चीनी जानकारों ने नई दिल्ली के प्रति वाशिंगटन के नजरिए को 'लिमिटेड इंगेजमेंट और सीलिंग कंट्रोल' की दोहरी रणनीति बताया। उसने तर्क दिया कि अलग-अलग राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं, विश्व व्यवस्था के नजरिए, भूराजनीतिक हितों, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और राजनयिक परंपराओं से पैदा हुए गहरे ढांचागत विरोधाभासों को भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक बातचीत या आर्थिक सहयोग से पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता।

सिंघुआ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियानफेंग ने सोमवार को ग्लोबल टाइम्स को बताया कि पिछले दो दशकों में अमेरिका-भारत संबंधों का तेजी से विस्तार एक हद तक पहुंच रहा है, क्योंकि दोनों देश ऐसे ढांचागत विरोधाभासों का सामना कर रहे हैं जिन्हें सुलझाना मुश्किल है। ये अंतर उनके विकास के अलग-अलग चरण, रणनीतिक संस्कृति, भूराजनीतिक स्थिति, राजनयिक परंपराओं और उनके नेतृत्व के विदेश नीति आधार से पैदा होते हैं। कियान ने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता, वॉशिंगटन के सहयोग आधारित दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। नई दिल्ली ने अमेरिका के रणनीतिगत मकसदों के साथ पूरी तरह से जुड़ने के बजाय, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लगातार एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। क्वाड और भारत-प्रशान्त रणनीति जैसे ढांचे के अंदर भी भारत अमेरिका के साथ एक औपचारिक सहयोगी या कनीय सुरक्षा भागीदार के बजाय एक बराबर के भागीदार के तौर पर जुड़ना चाहता है।

ऑफिशियल मीडिया में चीनी विशेषज्ञ की इस टिप्पणी से पता चलता है कि चीन अब भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने के लिए भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है और अपने पहले के इस रूख को नरम कर दिया है कि अमेरिका ने अपनी भारत-प्रशान्त रणनीति में भारत को एक भागीदार के तौर पर लिया है, जो मुख्य रूप से चीन के खिलाफ थी। चीनी विश्लेषक का जोर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए एक स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश कर रहे थे। चीनी विशेषज्ञ के मुताबिक लैंडाऊ की बातें भारत के प्रति वॉशिंगटन के बड़े दृष्टिकोण को दिखाती हैं, और वह है भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा में नई दिल्ली का समर्थन मांगते हुए उसे औद्योगिक श्रृंखला के निचले सिरे पर लॉक करना। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी रणनीति भारत के रणनीतिगत लक्ष्यों के खिलाफ है।

कियानफेंग के अनुसार, 'उद्योगीकरण सभी विकासशील देशों का एक कानूनी अधिकार है। जीरो-सम सोच (एक का लाभ दूसरे की हानि है) से प्रेरित होकर, अमेरिका दूसरे देशों के विकास पर एक सीमा लगाना चाहता है। टैरिफ और तकनीकी रुकावटों के जरिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तोड़कर, यह भारत को ब्रिक्स फ्रेमवर्क के साथ-साथ चीन और रूस के साथ सहयोग को और गहरा करने के लिए ही प्रेरित करेगा, जिससे औद्योगिक श्रृंखला के विविधिकरण में तेजी आएगी।' अभी भारत और अमेरिका 2026 के खत्म होने से बहुत पहले व्यापार समझौते को पूरा करने की दौड़ में लगे हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 99 प्रतिशत मुद्दे बातचीत में सुलझा लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापार का ढांचा लगभग तैयार है। लेकिन भारत-अमेरिका व्यापार बातचीत के आखिरी दौर में भी, अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत प्रतिबंध लगाने की बात कही। इसका मतलब था कि जांच के दायरे में आने वाले देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) पर 12.5 प्रतिशत ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी लैंडाऊ के बयान का लहजा कई व्यापार विशेषज्ञों की उन आशंकाओं को सही ठहराता है कि अमेरिका जल्दबाजी में भारत पर ऐसा व्यापार समझौता थोप रहा है जिसमें सिर्फ अमेरिका के हितों की रक्षा हो रही है, भारत के नहीं। अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार हिम्मत दिखाए और भारतीय किसानों और अन्य वर्गों के हितों की रक्षा करे, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी वातार्कार अपने किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसकी तरक्की इसके संसाधनों, मानव पूंजी और कई अन्य संपत्तियों पर निर्भर करती है। देश को निश्चित रूप से अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की जरूरत है। लेकिन यह समझौता बराबरी के आधार पर होना चाहिए। किसी भी देश को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की को दबाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देना ही अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाऊ को सबसे माकूल जवाब होगा। चीन ने ऐसा करके दिखाया है। भारत भी अमेरिका के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत करके ऐसा ही कर सकता है।

सात्यकी चक्रवर्ती

कहो तो कह दूं - जब तक मुर्दा ओटीपी, पासवर्ड नहीं बताएगा उसका फ्यूनरल नहीं हो पाएगा

आजकल ओटीपी और पासवर्ड को लेकर लोग भारी परेशान हैं ,हर जगह या तो पासवर्ड बताओ या फिर ओटीपी ,हाल तो ये है कि देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक से यदि एकमुश्त दस हजार रुपए एटीएम से निकालना चाहे तो वो पहले ओटीपी मांगता है इसलिए आजकल आदमी दो बार में पांच पांच हजार निकाल लेता है कि ओटीपी न बताना पड़े। ऑनलाइन सामान बुलवाओ डिलीवरी बॉय तब तक सामान नहीं देगा जब तक आप ओटीपी नहीं बताओगे। अरे भैया हमने पैसा दे दिया, तुम सामान ले आए, घर का पता तुम्हें मालूम है, घर में कोई पड़ोसी तो रहने आएगा नहीं, रहेगा तो वही आदमी जिसने आर्डर दिया होगा लेकिन नहीं पहले ओटीपी बताओ तब जाकर माल की डिलीवरी होगी। लोग बाग आजकल सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, सब पर लगे हुए लेकिन सबका पासवर्ड चाहिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो समझ लो आपका बंटाधार तय है। लाख कोशिश कर लो ना आपका फेसबुक खुलेगा, ना जीमेल खुलेगी, ना इंस्टाग्राम खुलेगा, ना व्हाट्सएप खुलेगा ,इतना तो बचपन में पाठ याद करने में टाइम नहीं लगता था जितना आजकल पासवर्ड याद रखने में लगता है। यही हाल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम का भी है सब में पहले पासवर्ड डालो तब जाकर पैसा निकलेगा कार्ड भी दसियों हो गए हैं एटीएम कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, समग्र आईडी का कार्ड, पैन कार्ड, एम्पलाई कार्ड और अब बच्चों के लिए अपार कार्ड भी बनाना तय हो गया है आदमी का पर्स कार्डों से भरा हुआ है कब कौन सा कार्ड सरकार मांग ले कोई भरोसा नहीं, किस कार्ड के आधार पर यह बता दिया जाए कि आप भारत के नागरिक नहीं है कोई कुछ नहीं कह सकता ।ओटीपी का तो हाल ये हो जाएगा कि प्रेमी प्रेमिका से बात करना चाहता है तो बोलेगी पहले ओटीपी बताओ तब बात करना, पति-पत्नी के साथ रोमांस करना चाहेगा तो पत्नी बोलेगी पहले पासवर्ड बताओ या फिर ओटीपी। हाल ये हो जायेंगे कि मरीज का अस्पताल में ऑपरेशन होना है वो ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ है डॉक्टर हाथ में कैंची चाकू लिए तैयार खड़ा है लेकिन तब तक ऑपरेशन नहीं कर रहा जब तक मरीज अपना पासवर्ड या ओटीपी नहीं बता देता मरीज मर जाए उससे कोई लेना-देना नहीं जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। ट्रेन में चढ़ता है तो ओटीपी के बना ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, बस से यात्रा करना है तो पासवर्ड चाहिए, प्लेन में बैठना है उसके पहले आपको पासवर्ड या ओटीपी बताना पड़ेगा तब आप यात्रा के लिए सूटेबल हो पाए हो पाओगे। अपने को तो लगता है कि वो दिन भू दूर नहीं है जब शमशान घाट में मुर्दे से भी पूछा जाएगा कि पहले ओटीपी बताओ पासवर्ड बताओ तभी तुम्हारा फ्यूनरल हो पाएगा वरना बॉडी ऐसे ही पड़ी रहेगी हो सकता है घर वाले तेरहवीं कर दें बरसी भी हो जाए लेकिन फ्यूनरल ना हो पाए बिना ओटीपी या बिना पासवर्ड के।

एक बड़ी मजेदार खबर अखबार में आई है। लुधियाना में एक सेवानिवृत अधिकारी थे कहीं बाहर गए थे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, रात को दो बजे अचानक नींद खुली और उन्होंने देखा कि उनके घर में कुछ लोग घुस रहे उन्होंने तुरंत पड़ोसी के बेटे को फोन किया और उसने पुलिस को फोन किया कि पड़ोस वाले अंकल के सूने घर में चोर घुसे हुए हैं आप लोग जल्द आ जाइए, तो पुलिस वालों ने जवाब दिया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है हम नहीं आ पाएंगे। आम आदमी इसमें पुलिस का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं अरे भाई इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है हो सकता है सरकार ने उन्हें बरसाती ना दी हो, इतनी तेज बारिश में सड़क में कौन से गड्ढे में गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी बारिश में चलना खतरनाक होता है, ना सामने कुछ दिखता है ना पीछे कौन आ रहा है ये दिखाई देता है सही तो कहां पुलिस ने बारिश तेज है ।चूंकि मामला बरसात का था इसलिए बारिश तेज का बहाना बन गया भविष्य में यदि कोई गर्मी में कंप्लेंट करेगा तो ये कहा जाएगा भैया बाहर लू चल रही है हम नहीं आ पाएंगे, यही हाल ठंड का होगा कि बाहर कड़कड़ाती ठंड है हम थाने से बाहर निकले तो निकलें कैसे? फिर दूसरी बात जब तक पुलिस उनके घर तक पहुंचती तब तक तो चोर महोदय अपना काम करके निकल लिए होते,पुलिस ने भी सोचा होगा कि जब चोर पकड़ में ही नहीं आना है तो काहे को इतनी कवायत करो ।लुधियाना पुलिस ने जो भी किया था सही किया और इसी चक्कर में चोर लाखों का माल लूट के निकल गया

कांग्रेस में इस समय भारी जंग चल रही है एक नेता दूसरे नेता की जड़ खोदने में लगा है जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश करते हुए बहुत बड़ा गुब्बारा फुलाया लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक छोटी सी सुई से उस गुब्बारे की पूरी हवा निकल कर रख दी। इधर कांग्रेस महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका करारजिन पर जिम्मेदारी थी कि वे महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दें उनकी पार्टी ने उनको ही नोटिस देकर उनका उत्पीड़न कर दिया, अब बेचारी सोशल मीडिया पर अपना दुखड़ा रो रही हैं कि नोटिस के नियम क्या महिलाओं के लिए ही हैं उधर दिग्विजय सिंह के खिलाफ निधि चतुवेर्दी ने जो पोस्ट लिखी उस पर उनको भी नोटिस मिल गया जबकि पार्टी में ये कहां जा रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा लेकिन सवाल ये है कि जो महिला महिलाओं की उत्पीड़न के लिए बनाए गए प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अपना ही नोटिस रूपी उत्पीड़न नहीं रोक पा रही है उसे नोटिस दिया जा रहा है तो फिर वह दूसरी महिलाओं के उत्पीड़न को क्या खाक रोक पाएगी? वैसे उसका कहना सही है कि बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दलाल और ब्लेकमेलर कह दिया उनको तो आज तक कोई नोटिस नहीं मिला आखिर ऐसा पार्टी में क्यों हो रहा है लेकिन अपने को मालूम है कि कांग्रेस को किसी चीज से कोई लेना-देना नहीं पार्टी जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी भले ही बीच-बीच में तरह-तरह के बयान आते रहे लेकिन होना जाना कुछ नहीं है ये अपने को भी मालूम है और हर कांग्रेसी को भी। अजी सुनते हो, हमारी शादी कराने वाले पंडित जी का देहांत हो गया ।श्रीमती जी ने श्रीमान जी से कहा मैं तो पहले ही कहता था कि जिस दिन उसने हमारी शादी करवाई थी उसी दिन तय हो गया था एक न एक दिन उसे उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी!श्रीमान जी ने उत्तर दिया।

(लेखक-चैतन्य भट्ट)

दलबदल, यानी जनादेश से विश्वासघात

भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस जनादेश और विश्वास का सम्मान करना भी होता है जिसके आधार पर मतदाता उन्हें चुनते हैं। किंतु पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में दलबदल की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, उसने लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक नैतिकता और जनमत की गरिमा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

हाल के महीनों में पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बड़ी संख्या में सांसदों और विधायकों द्वारा पार्टी बदलने की घटनाओं ने इस बहस को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। राजनीतिक दलों के बीच नेताओं का आना-जाना कोई नई घटना नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय राजनीति में दलबदल होता रहा है, लेकिन वर्तमान दौर में इसकी प्रकृति और स्वरूप बदल गया है। पहले व्यक्तिगत स्तर पर दलबदल होता था, जबकि अब बड़ी संख्या में सांसदों और विधायकों को एक साथ संगठित करके कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे ह्यसामूहिक दलबदलह्न या ह्यस्मार्ट मर्जरह्न की राजनीति के रूप में देख रहे हैं।

दलबदल के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। सत्ता के निकट पहुंचने की इच्छा, धन पिपासा, मंत्री पद या संगठनात्मक जिम्मेदारियों की आकांक्षा, चुनावी टिकट की अनिश्चितता, पार्टी नेतृत्व से असंतोष, वैचारिक मतभेद अथवा क्षेत्रीय विकास के नाम पर सत्तारूढ़ दल से निकटता, ये सभी कारण अक्सर सामने आते हैं। किंतु लोकतांत्रिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कोई जनप्रतिनिधि उस राजनीतिक दल को छोड़ सकता है जिसके चुनाव चिन्ह और विचारधारा के आधार पर जनता ने उसे चुना था। इसी समस्या को रोकने के लिए वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और व्यक्तिगत लाभ के लिए होने वाले दलबदल को रोकना था। इस कानून के अनुसार यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है अथवा पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि समय के साथ इस कानून की सीमाएं भी सामने आईं। प्रारंभ में एक-तिहाई सदस्यों के टूटने पर छूट का प्रावधान था, जिसे 91वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि किसी दल के कम से कम दो-तिहाई सांसद या विधायक सामूहिक रूप से किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो उन्हें अयोग्यता से संरक्षण मिल जाता है। यही प्रावधान आज सबसे अधिक विवाद का विषय बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि यह व्यवस्था व्यक्तिगत दलबदल को तो दंडित करती है, लेकिन सामूहिक दलबदल को वैधता प्रदान कर देती है। 2023 में महाराष्ट्र से जुड़े सुभाष देसाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विधायकों या सांसदों का समूह स्वयं को मूल पार्टी नहीं मान सकता। वैध विलय के लिए मूल राजनीतिक दल और विधायी दल दोनों स्तरों पर निर्धारित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। दलबदल का मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक दल और नेता कानून की उन खामियों का लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं जो सामूहिक विलय को संरक्षण प्रदान करती हैं। यही कारण है कि आज संविधान विशेषज्ञ, विधि आयोग और चुनाव सुधारों के पक्षधर व्यापक संशोधन की मांग कर रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मत है कि यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए और उसे पुनः जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसके निर्णय को वास्तव में जनता का समर्थन प्राप्त है या नहीं। कुछ विशेषज्ञ ऐसे नेताओं पर पांच वर्ष तक चुनाव लड़ने अथवा मंत्री बनने पर रोक लगाने की भी वकालत करते हैं। इससे राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने वाले अवसरवादी दलबदल में कमी आ सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि दलबदल संबंधी मामलों का निर्णय स्पीकर के बजाय किसी स्वतंत्र न्यायिक अधिकरण अथवा चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था को सौंपा जाए। वर्तमान व्यवस्था में अक्सर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं क्योंकि स्पीकर स्वयं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के अनुभव भी इस बहस को नई दिशा देते हैं। ब्रिटेन में सांसदों को पार्टी बदलने की स्वतंत्रता है, लेकिन वहां राजनीतिक नैतिकता और मतदाताओं की जवाबदेही इतनी मजबूत है कि दलबदल करने वालों को अक्सर जनता चुनाव में दंडित कर देती है। अमरीका में भी दलबदल विरोधी कानून नहीं है।

भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट है कि न तो पूर्ण स्वतंत्रता उपयुक्त होगी और न ही वर्तमान व्यवस्था की सभी कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता केवल कानूनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि राजनीतिक नैतिकता, जन-जागरूकता और संस्थागत निष्पक्षता पर भी आधारित होती है। अंततः दलबदल का प्रश्न केवल सांसदों और विधायकों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास का प्रश्न है। यदि मतदाता किसी विशेष विचारधारा, नेतृत्व और चुनाव चिन्ह को ध्यान में रखकर अपना मत देता है, तो उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सत्ता परिवर्तन जनता के मत से हो, न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामूहिक पाला बदलने से। जनता को भी चाहिए कि वह चुनाव के समय दलबदलू नेताओं को हराकर अच्छा सबक सिखाए। यह समय की मांग है कि दलबदल विरोधी कानून की समीक्षा कर उसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए, ताकि लोकतंत्र की आत्मा और मतदाता के विश्वास, दोनों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

आचार्य, लेखक बैजनाथ से हैं

विश्व जनसंख्या दिवस पर विशेष

पृथ्वी पर तेजी से बढ़ती जनसंख्या : विकास, संसाधन और भविष्य की चुनौती

मानव सभ्यता के विकास का इतिहास जितना पुराना है, जनसंख्या वृद्धि का इतिहास भी उतना ही पुराना है। प्राचीन काल में अधिक जनसंख्या को शक्ति, समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। कृषि प्रधान समाजों में अधिक हाथों का अर्थ अधिक उत्पादन और अधिक सुरक्षा समझा जाता था।

भारत सहित विश्व की अनेक संस्कृतियों में विवाह और संतानोत्पत्ति को जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। उस समय पृथ्वी पर जनसंख्या कम थी, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त थे और मानव बसाहटें सीमित थीं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता था। किन्तु समय के साथ परिस्थितियाँ बदल गईं।

औद्योगिक क्रांति, चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, टीकाकरण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और घटती मृत्युदर के कारण विश्व की जनसंख्या अभूतपूर्व गति से बढ़ने लगी। आज स्थिति यह है कि जनसंख्या वृद्धि केवल संख्या का प्रश्न नहीं रह गई है, बल्कि यह विकास, पर्यावरण, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ा वैश्विक विषय बन चुकी है। इसी गंभीर चुनौती के प्रति विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में इस दिवस की शुरूआत की थी। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या पाँच अरब के आँकड़े तक पहुँच गई थी, जिसे ₹फाइव बिलियन डे₹ कहा गया। उसी घटना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाने लगा।

आज विश्व की जनसंख्या लगभग आठ अरब से अधिक हो चुकी है। वैज्ञानिकों और जनसंख्या विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या लगभग 9.7 अरब तक पहुँच सकती है। यद्यपि कई विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो रही है, फिर भी विकासशील देशों में बढ़ती आबादी संसाधनों पर भारी दबाव बना रही है।

भारत के संदर्भ में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। स्वतंत्रता के समय देश की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी। 1951 की पहली जनगणना में यह लगभग 36 करोड़ थी, जो आज बढ़कर लगभग 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह वृद्धि केवल संख्या में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि इसके साथ अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। पृथ्वी के पास सीमित भूमि, जल, वन और खनिज संसाधन हैं, जबकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। परिणामस्वरूप कृषि भूमि सिकुड़ रही है, भूजल स्तर घट रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है और जैव विविधता संकट में पड़ रही है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर बढ़ता दबाव पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है।

जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध बेरोजगारी से भी है। जब रोजगार सृजन की गति जनसंख्या वृद्धि की गति से पीछे रह जाती है, तब बेरोजगारी और आर्थिक विषमता बढ़ने लगती है। लाखों शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं, जबकि सीमित अवसरों के कारण प्रतिस्पर्धा और अधिक कठिन हो जाती है। यही स्थिति सामाजिक असंतोष और आर्थिक असुरक्षा को जन्म देती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनसंख्या वृद्धि बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बढ़ती आबादी के कारण विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर दबाव बढ़ रहा है। सरकारों को अधिक संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना कठिन हो जाता है।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण की समस्या भी जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई है। रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ।परिणामस्वरूप महानगरों में झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ रही हैं, यातायात की समस्याएँ गंभीर होती जा रही हैं तथा पेयजल, स्वच्छता और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ता है। अधिक जनसंख्या का अर्थ अधिक ऊर्जा खपत, अधिक वाहन, अधिक उद्योग और अधिक कार्बन उत्सर्जन है। इससे वैश्विक तापमान वृद्धि, जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

हालाँकि यह भी सत्य है कि जनसंख्या केवल समस्या नहीं है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और उत्पादक हो तो वही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यदि इस जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ, तो यही जनसंख्या भारत के विकास का आधार बन सकती है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और परिवार नियोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना जनसंख्या स्थिरीकरण का सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। अध्ययन बताते हैं कि जहाँ महिला शिक्षा का स्तर ऊँचा होता है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर स्वतः नियंत्रित हो जाती है। बाल विवाह, लैंगिक असमानता, अशिक्षा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियाँ भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती हैं। इसलिए समाज को वैज्ञानिक सोच अपनानी होगी। छोटा परिवार न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है, बल्कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए भी आवश्यक है।

यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जनसंख्या और विकास के बीच संतुलन स्थापित किए बिना सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते।

बढ़ती जनसंख्या मानवता के सामने उपस्थित सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, किन्तु सही नीतियों, जन-जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इसे अवसर में भी बदला जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम संख्या की वृद्धि के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान दें। ₹छोटा परिवार केवल एक नारा नहीं, बल्कि समृद्ध, स्वस्थ और संतुलित भविष्य की आधारशिला है।₹ विश्व जनसंख्या दिवस पर, हम जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने का संकल्प लें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध पृथ्वी प्रदान की जा सके।

संक्षिप्त वार्ता

यमुना विहार के सरकारी विद्यालयों में सुधार की मांग

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। यमुना विहार वार्ड संख्या 232 के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने की मांग उठी है। यमुना विहार ब्लॉक कांग्रेस के सचिव रूबल सक्सेना ने विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, शिक्षण व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया।

रूबल सक्सेना ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन, स्वच्छ पेयजल, बेहतर फर्नीचर तथा प्रत्येक कक्षा में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति, नियमित परामर्श व्यवस्था तथा विज्ञान और संगणक प्रयोगशालाओं को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने की आवश्यकता भी बताई।

जलभराव पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में लगातार दूसरे दिन हुई वर्षा के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव और यातायात बाधित होने की घटनाओं को लेकर आजादपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भारत सिंह राघव ने दिल्ली सरकार और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून की शुरूआती वर्षा ने राजधानी की जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। भारत सिंह राघव ने कहा कि अनेक प्रमुख मार्गों, गलियों और रिहायशी क्षेत्रों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि कई स्थानों पर लंबे यातायात जाम लगे, जिससे कार्यालय आने-जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

बरसात में सरकार के दावों पर उठे सवाल

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में लगातार हुई वर्षा के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को लेकर राम नगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप भाटी ने दिल्ली सरकार और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन की वर्षा ने मानसून से निपटने के सरकारी दावों की वास्तविकता सामने ला दी है।

कुलदीप भाटी ने कहा कि सरकार लंबे समय से जलभराव मुक्त दिल्ली का दावा कर रही थी, लेकिन वर्षा के बाद अनेक क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो गईं। उनका आरोप है कि जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हुई और विद्यार्थियों को भी पानी से होकर विद्यालय जाना पड़ा।

जहांगीरपुरी में जलभराव पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में मानसून की पहली तेज वर्षा के बाद जहांगीरपुरी क्षेत्र में हुए जलभराव को लेकर रोहिणी जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष एम. एल. भास्कर ने सरकार और संबंधित विभागों की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहली ही वर्षा ने जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है।

एम एल. भास्कर ने क्षेत्र का दौरा करने के बाद कहा कि समय पर नालों की प्रभावी सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता तो लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि कई नाले गाद और कचरे से भरे होने के कारण वर्षा का पानी सड़कों और गलियों में भर गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही वर्षा में हालात बिगड़ जाना तैयारियों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उनका कहना है कि कई स्थानों पर लोगों के घरों और दुकानों तक पानी पहुंच गया, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली के पुर्नविकास को दी नई दिशा

इंद्रप्रस्थ विरासत पुर्नविकास निगम के साथ लौटेगा पुरानी दिल्ली का गौरव

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को उसके मूल गौरव के साथ पुनर्जीवित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने पुरानी दिल्ली के संरक्षण व पुनर्विकास के उद्देश्य से गठित शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की व्यापक और गंभीर पहल प्रारंभ हो चुकी है।

इसी क्रम में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की चेयरपर्सन व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में निगम की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास मंत्री एवं निगम के उपाध्यक्ष श्री आशीष सूद, प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का डिजाइन इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए क्षेत्र में आधुनिक एवं उपयोगी सार्वजनिक शौचालय (टॉयलेट ब्लॉक) विकसित किए जाएं और नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसका एक प्रमुख प्रवेश एवं निकास चांदनी चौक की ओर से भी विकसित किया जाए ताकि यह ऐतिहासिक इमारत एक प्रमुख विरासत एवं पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सके। बैठक में स्थानीय व्यापारियों व दुकानदारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखने पर बल दिया गया ताकि विरासत संरक्षण और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री का कहना था कि जब से चांदनी चौक का विकास हुआ है, तभी से यहां बाजार विकसित हुआ था, इसलिए इस बाजार का गौरव वापस लौटाने में यहां के बाजार, व्यापारियों व दुकानदारों का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि चादनी चौक का विकास यहां के बाजारों, पर्यटकों, खरीदारों और स्थानीय निवासियों के हितों के ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पुरानी दिल्ली का विकास केवल भौतिक आधारभूत संरचना तक सीमित न रहे, बल्कि विरासत का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों, नागरिक सुविधाओं व पर्यावरणीय संतुलन को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम अब विरासत संरक्षण और आधुनिक शहरी विकास को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। इसके तहत ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण, आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार व अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। इसलिए विकास कार्य ऐसे हों, जिनसे पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और स्थापत्य सौंदर्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विकास साथ-साथ होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को बेहतर सुविधाएं मिलें और पुरानी दिल्ली एक विश्वस्तरीय विरासत क्षेत्र के रूप में अपनी नई पहचान बना सके।

कार्ययोजना तैयार करने दिये निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार में एक समर्पित कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग सुविधाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया, जिससे आगंतुकों को आवागमन और वाहन पार्किंग में सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस व्यापक परियोजना में यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर एवं उसके पीछे के क्षेत्र के समग्र विकास का भी विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त जामा मस्जिद क्षेत्र और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के समग्र सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मेट्रो की मैजेंटा लाइन बनेगी नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर

नई दिल्ली, वेब वार्ता

मेट्रो की मैजैंटा लाइन भविष्य में दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनने जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की शुरूआत की गई, जो इस महत्वपूर्ण परियोजना का पहला निर्माण चरण है। 12.377 किलोमीटर लंबा इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर बनने के बाद मैजेंटा लाइन की लंबाई कुल 89 किलोमीटर हो जाएगी जो दिल्ली में सबसे ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि विकसित दिल्ली की आधारशिला है। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क का निरंतर विस्तार नागरिकों को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कॉरिडोर पर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सात प्रमुख लाइनों से यह मैजेंटा लाइन जुड़ेगी। इसमें इंद्रलोक स्टेशन पर रेड एवं ग्रीन लाइन, नबी करीम पर मैजेंटा लाइन, नई दिल्ली स्टेशन पर येलो एवं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, दिल्ली गेट पर वायलेट लाइन और इंद्रप्रस्थ स्टेशन पर ब्लू लाइन से इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। अधिक नागरिकों के सार्वजनिक परिवहन से जुड़ने पर निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम, ईंधन की खपत एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी नई मजबूती मिलेगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी को विश्वस्तरीय, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है।

दिल्ली के प्रमुख संस्थानों तक बेहतर पहुंच

यह नया मेट्रो कॉरिडोर सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली सचिवालय, झंडेवालान मंदिर, अरुण जेटली स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली गेट, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और सेंट्रल विस्टा जैसे कई महत्वपूर्ण स्थानों को बेहतर और निर्बाध मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, पर्यटकों और रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

महत्वपूर्ण स्टेशन

- सराय रोहिल्ला स्टेशन इस कॉरिडोर के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक होगा।
- बॉटनिकल गार्डन से आरके आश्रम तक है मैजेंटा लाइन
- मैजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम से आर. के. आश्रम मार्ग वाले कॉरिडोर पर निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। इसमें से जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन (1.8 किमी) और दीपाली चौक से मजलिस पार्क (9.9 किमी) वाले हिस्से पहले ही परिचालित हो चुके हैं, जबकि बाकी हिस्से अलग-अलग चरणों में खुलेंगे।
- सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर पर भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक यह लाइन तीसरे फेज में ही तैयार कर ली गई थी।

तिहाड़ में कैदियों को सुविधा दिलाने का झांसा देकर ठग रहे रकम

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में बंद कैदियों और उनके परिजनों से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। कैदियों को जेल में विशेष सुविधा मुहैया करने का झांसा देकर ठगी की जा रही है। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 28520414 जारी किया है। साथ ही कैदियों के परिजनों व अन्य लोगों से अपील की है कि जेल कर्मचारी बनकर अगर कोई रुपये की मांग करता है, तो तुंरत हेल्पलाइन नंबर पर उसकी शिकायत करें।

जेल अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग खुद को जेल अधिकारी और कर्मचारी बताकर कैदियों के परिजनों से संपर्क कर रहे हैं। ये आरोपी कैदी को मोबाइल सुविधा, बेहतर बैरक, मुलाकात की व्यवस्था, जेल स्थानांतरण या अन्य विशेष सुविधाएं दिलाने का दावा करते हैं। इसके बदले में परिजनों से मोटी रकम की मांग की जाती है। परिजनों को झांसे में लेने के लिए आरोपी, कैदी और उससे जुड़े केस की सभी जानकारी परिजनों को बता कर उनका भरोसा हासिल करते हैं। फिर रकम लेकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं।

जेल अधिकारी ने बताया कि कई मामलों की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कैदियों के परिवारों की जानकारी जुटाकर उन्हें फोन किया या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर संपर्क किया। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने खुद को जेल अधीक्षक बताकर ठगी को अंजाम दिया था।

डीयू में दाखिले से पहले बनवा लें सही प्रमाणपत्र

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्नातक दाखिले के लिए सीएसएएस पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। डीयू ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपने प्रमाणपत्रों की जांच कर लेनी चाहिए।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रारूप और वैध प्रमाणपत्र नहीं होने पर आरक्षित श्रेणी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों में दाखिला रद्द हो सकता है। डीयू के अनुसार, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र 31 मार्च 2026 के बाद जारी होना चाहिए। इससे पहले जारी प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस (आय एवं संपत्ति) प्रमाणपत्र भी 31 मार्च 2026 के बाद जारी होना चाहिए। पुराना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीयू के सूचना बुलेटिन के अनुसार, एससी-एसटी अभ्यर्थियों के पास अपने नाम से जारी वैध जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। प्रमाणपत्र में जाति का नाम, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार की अनुसूची का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश के समय मूल प्रमाणपत्र पेश करना जरूरी होगा। इसी तरह ओबीसी-एनसीएल अभ्यर्थियों को केवल केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल जाति का प्रमाणपत्र मान्य होगा।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पुलिस पर सख्ती, 11 लाइन हाजिर

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पिछले 10 दिनों में एक थानाध्यक्ष सहित 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। कार्रवाई लापरवाही, अवैध गतिविधियों की अनदेखी तथा अपराधियों के प्रति कथित नरमी बरतने के आरोपों में की गई है। वहीं विभाग के 33 अन्य पुलिसकर्मी भी अधिकारियों की निगरानी में बताए जा रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में एक थानाध्यक्ष, सहायक उपनिरीक्षक तथा आरक्षी शामिल हैं। सोनिया विहार क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और एक आरोपी के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में थानाध्यक्ष पंकज सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। इसी प्रकार नंद नगरी थाने के अभिलेख प्रभारी तथा तीन बीट आरक्षियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इन पर अवैध शराब और सट्टे जैसी गतिविधियों को संरक्षण देने के आरोप हैं। इसके अलावा विशेष दल के सहायक उपनिरीक्षक पवन मलिक सहित अन्य पुलिसकर्मियों को विभिन्न मामलों में लापरवाही के कारण लाइन हाजिर किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि 9 आरक्षियों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके कार्यक्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। जिला पुलिस कार्यालय स्तर पर कराई गई जांच में कई शिकायतें सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार फिलहाल 3 थानाध्यक्ष, 2 उपनिरीक्षक और 28 आरक्षी भी अधिकारियों की निगरानी में हैं। यदि जांच में उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित होते हैं तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस विभाग में लाइन हाजिर किए जाने का अर्थ संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को क्षेत्रीय ड्यूटी से हटाकर जिला पुलिस लाइन में भेजना होता है। वहां उन्हें आरक्षित ड्यूटी अथवा अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है। विभागीय व्यवस्था में इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। अपराध और पुलिसकर्मियों की कथित संलिप्तता से संबंधित शिकायतों के लिए उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने अपने कार्यालय के बाहर गुप्त सूचना पेटी भी स्थापित कराई है। इस पेटी को स्वयं खोलकर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में 10 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई प्रथम दृष्टया सही पाई गईं। इनके आधार पर अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा संबंधित पुलिसकर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। राहुल अलवाल ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी भी आपराधिक गतिविधि में किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पेंशन विसंगति पर 22 जुलाई को होगा धरना

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के संगठन पेंशन फाइटर्स ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। संगठन ने दिल्ली पुलिस को 15 दिनों का नोटिस सौंपते हुए 22 जुलाई को संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना देने की घोषणा की है। संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, महासचिव सैयद खालिद अकबर और संयोजक सुनील गुप्ता ने आरोप लगाया कि 1 जनवरी 2006 से कई संवर्गों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मूल पेंशन का निर्धारण सही ढंग से नहीं किया गया है। उनका कहना है कि अन्य उत्तराधिकारी संस्थानों ने इस विसंगति को दूर कर सही पेंशन लागू कर दी है, जबकि संबंधित कंपनी में अब भी त्रुटियां बनी हुई हैं।

दिल्ली रोहिणी हादसा: रातभर मलबे में जिंदगी की तलाश, सुबह तक मिली 4 की लाश

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 में बुधवार को तीन मंजिला निमार्णाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को मजदूर को जिंदा बचाया गया है। रोहिणी के सेक्टर 26 में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियों ने रातभर राहत और बचाव का अभियान चलाया। मलबे में जिन लोगों के शव बरामद किए गए हैं उनमें वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार, श्रमिक और मकान मालिक के पिता शामिल हैं।

मलबे से 32 साल के सद्दाम उर्फ रवि को जिंदा बचाया गया था। मृतकों की पहचान रोहिणी सेक्टर 16 निवासी टेलर राम (42), काफे उर्फ नुरुल (24) निवासी द्वारका, राम दुआ (62) निवासी सेक्टर 16, रोहिणी के रूप में हुई है। राम दुआ का बेटा ही इस इमारत का निर्माण करा रहा था। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रोहिणी सेक्टर 16 के जी ब्लॉक में 26-26 गज के दो प्लॉट को जोड़कर तीन मंजिला इमारत बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार, बुधवार को इमारत के अंदरुनी हिस्से में काम चल रहा ता। शाम चार बजे इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। दमकल अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया। तीन घंटे की मशक्कत के बाद 32 वर्षीय सद्दाम को मलबे से जीवित निकाला गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

चार मंजिला इमारत के मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रातभर अभियान चलता रहा। दमकल और एनडीआरएफ के 120 अधिकारी और जवान हल्की बारिश के बीच भी बचाव में लगे रहे। बचाव दल में शामिल एक सदस्य ने बताया कि यह इमारत एक तरह से धंस गई है। इसलिए एक छत दूसरे पर गिरी है। ऐसे में ज्यादा मलबा हटाना पड़ रहा था और सावधानी पूर्वक यह काम किया जा रहा था। इसलिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। द्वारका से एनडीआरएफ की विशेष टीम साजोसामान और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची।

सरकारी जमीन पर कब्जे पर बिना सूचना चलेगा बुलडोजर: डीडीए

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा, निर्माण अथवा अवैध उपयोग पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि उसके संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं ने प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है अथवा उसका अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि उसके अधिकार अथवा स्वामित्व वाली सभी भूमि सरकारी संपत्ति है। सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता, किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता, भवन खड़ा नहीं कर सकता, मलबा या सामग्री नहीं डाल सकता तथा अनधिकृत वाहन पार्किंग या किसी अन्य प्रकार का अवैध उपयोग भी नहीं कर सकता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी भूमि पर किसी प्रकार का अनधिकृत कब्जा पाया जाता है तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल हटाया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई से संबंधित सभी जोखिम, दायित्व और व्यय की जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकर्ता की होगी।

प्राधिकरण ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने अथवा अतिक्रमण हटाने में होने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूला जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जारी की गई यह सार्वजनिक सूचना सभी अतिक्रमणकताओं के लिए स्थायी सूचना मानी जाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे उसकी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा न करें। साथ ही किसी भी संपत्ति की खरीद, बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति ने पहले से प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, तो उसे तत्काल हटाने की सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में प्राधिकरण ने यह चेतावनी जारी करते हुए लोगों को कानून का पालन करने की सलाह दी है।

82 रुपये लीटर मिले पेट्रोल, ई20 वाला तो 70 का; अरविंद केजरीवाल का क्या गणित

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल कमी करने की मांग करते हुए दावा किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में पेट्रोल की कीमत अधिकतम 82 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिश्रित ईंधन वाला पेट्रोल इससे भी सस्ता, लगभग 70 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध कराया जा सकता है। उनका कहना है कि यदि ईंधन की कीमतें घटती हैं तो महंगाई पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल रह गई है, जबकि पहले यह 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। उनके अनुसार मौजूदा विनिमय दर के आधार पर कच्चे तेल की कीमत लगभग 42 रुपये प्रति लीटर बैठती है। इसमें शोधन, परिवहन, तेल कंपनियों का लाभ, केंद्रीय कर, मूल्य वर्धित कर तथा विक्रेता कमीशन जोड़ने के बाद भी पेट्रोल की कीमत लगभग 82 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मिश्रित ईंधन वाले पेट्रोल की कीमत इससे भी कम होकर लगभग 70 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार डीजल के दामों में भी कमी की जानी चाहिए, जिससे परिवहन लागत घटेगी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के उस संभावित तर्क को भी खारिज किया, जिसमें युद्ध के दौरान तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई वर्तमान लाभ से किए जाने की बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद कई अवसर ऐसे आए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन उसके अनुरूप उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी गई।

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में तेल कंपनियों ने भारी लाभ अर्जित किया है। उनके अनुसार पिछले वर्ष कंपनियों को लगभग 77 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ, जबकि उससे पहले के दो वर्षों के लाभ को जोड़ने पर यह आंकड़ा लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचता है।

70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य, हरित दिल्ली पर जोर

नई दिल्ली, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। भाजपा उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष डॉ यूके चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना और हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। डॉ यूके चौधरी ने कहा कि सरकार स्वच्छ परिवहन, हरित क्षेत्रों के संरक्षण, देशी प्रजातियों के पौधारोपण, वायु गुणवत्ता में सुधार, कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

संक्षिप्त वार्ता

हरदोई में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, वर्ल्ड बैंक की संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 9 जुलाई। जनपद में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार, एनएफडीपी, मत्स्य निदेशालय लखनऊ एवं मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न मत्स्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया।

सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. मुनीश कुमार ने बताया कि टीम ने सबसे पहले संडीला तहसील के ग्राम लोनहारा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी अंकित विशाल के वृहद आरएएस एवं कच्चे तालाबों का निरीक्षण किया। यहां पंगास और देशी मांगुर मछलियों के पालन की व्यवस्था का अवलोकन किया गया। इसके बाद टीम ने ग्राम सुहासा में हनीफ अली की मत्स्य हैचरी का निरीक्षण किया, जहां पंगास एवं आईएमसी (इंडियन मेजर कार्प) की ब्रीडिंग प्रक्रिया देखी गई। साथ ही पीएमएमकेएसएसवाई योजना के विभिन्न कंपोनेंट्स का भी परीक्षण किया गया।

हाथरस में मातृत्व मेले में 112 गर्भवती महिलाओं ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण,मिली जानकारी

हाथरस, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के सादाबाद में गुरुवार को आयोजित मातृत्व मेले में 112 महिला गर्भवती ने लाभ लिया। यह आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया।

महिला चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और वजन सहित विभिन्न प्रसव पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण किए। इस दौरान 11 गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज और तीन महिलाओं को एफसीएम इंजेक्शन भी लगाए गए। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, नियमित जांच, समय पर टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही, उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार की मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए परामर्श दिया गया।

होटल से पर्यटक का बैग चोरी करने वाले युवक-युवती गिरफ्तार, दो लैपटॉप समेत पूरा सामान बरामद

वाराणसी, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। दशाश्वमेध थाना पुलिस ने होटल से पर्यटक का बैग चोरी की घटना का खुलासा करते हुए युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी गए दो लैपटॉप, चार्जर, किताबें, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चश्मे, ईयरबड्स समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। पुलिस दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। थानाध्यक्ष दशाश्वमेध के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार दोपहर पत्थर गली स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में छापेमारी कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान विकाश पाण्डेय (28) पुत्र राकेश चंद्र पाण्डेय निवासी गड़ैया खुर्द, जारी थाना कौंधियारा, प्रयागराज के रूप में हुई है। उसके साथ 21 वर्षीय महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पुलिस ने उसकी पत्नी बताया है। दोनों के खिलाफ थाना दशाश्वमेध में दर्ज मुकदमा संख्या 148/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 305 एवं 317(2) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

औरैया में हाईवे पर ट्रेलर-ट्रक की भीषण भिड़ंत में क्लीनर की मौत, चालक समेत दो घायल

औरैया, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कोतवाली क्षेत्र में इटावा-औरैया हाईवे पर ग्राम बाकरपुर के सामने गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ यातायात सुचारु कराया। कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह के अनुसार गुरुवार तड़के करीब 1:35 बजे राजस्थान नंबर RJ-11 GC-7926 ट्रेलर और तेलंगाना नंबर TS-03 UC-0678 ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार क्लीनर मोहित (22) पुत्र अशोक ठाकुर, निवासी नौनी, थाना गजनेर, जनपद आगरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक रेमा रेड्डी और क्लीनर रामबाबू केबिन में बुरी तरह फंस गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त केबिन को हटाकर दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस से दोनों घायलों को 50 शैय्या जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है।

25 हजार का इनामी गिरफ्तार, कई भीषण चोरियों को दिया अंजाम, चोरी के जेवर गलाकर बना डाले सोने-चांदी के बिस्किट

वाराणसी, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। सारनाथ थाना पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की संयुक्त टीम ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश चित्रांश खरवार उर्फ चीकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के जेवरों को गलाकर तैयार किए गए सोने और चांदी के बिस्किट, एक सोनी डीएसएलआर कैमरा तथा 67 हजार रुपये नकद बरामद किए। आरोपी पर वाराणसी के विभिन्न थानों में चोरी और चोरी के माल की खरीद-फरोख्त समेत 19 मुकदमे दर्ज हैं।

नघेटा रोड पर धान रोपकर और कीचड़ में भाजपा के झंडे लगाकर सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने जताया विरोध

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 9 जुलाई। नगर की बदहाल सड़कों और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी रामज्ञान गुप्ता ने नघेटा रोड पर धान की रोपाई कर तथा कीचड़ में भाजपा के झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि थोड़ी सी बारिश में ही शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो जाता है, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि नघेटा रोड के अलावा मेडिकल कॉलेज, आरआर इंटर कॉलेज, बाल विद्या भवन मार्ग, मन्ना पुरवा के निकट लखनऊ मार्ग, बिलग्राम चुंगी मार्ग, मंगली पुरवा, गंगा देवी कॉलेज रोड तथा बिलग्राम रोड सहित कई स्थानों पर जलभराव के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उनका आरोप है कि जल निकासी के लिए मिले बजट का समुचित उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण नागरिकों को हर वर्ष इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि जलभराव और खराब सड़कों से छात्र-छात्राएं, मरीज, व्यापारी और आम नागरिक परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सड़क पर धान की रोपाई कर प्रशासन से जल्द जल निकासी और सड़क मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों ने भी नगर की बदहाल सड़कों और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। इस अवसर पर समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष सुधीर गुप्ता 'मिन्ना', अवनीश यादव, धर्मेंद्र यादव 'दीपू', चंद्रप्रकाश गुप्ता, रामदत्त गुप्ता, शुभम गुप्ता, श्याम गुप्ता, दुर्गेश, रिंकू गुप्ता, हरिश्चंद्र, रमेश यादव, विनय सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विश्वनाथ धाम में काशीवासियों के लिए खुला काशी द्वार

वाराणसी,वेब वार्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद काशीवासियों के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का काशी द्वार पूरे दिन के लिए खोल दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा काशीवासियों की सुविधा के लिए 2024 में द्वार संख्या 4-बी को ₹काशी द्वार₹ के रूप में चिह्नित किया गया था, जहां पहले सुबह-शाम प्रतिदिन 4 से 5 बजे तक विशेष दर्शन की व्यवस्था थी। अब इसे विस्तार देते हुए पूरे दिन के लिए खोल दिया गया है। इस द्वार से प्रवेश के लिए काशीवासियों को स्थानीय पते का पहचान पत्र दिखाना होगा।

काशीवासियों को अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। योगी सरकार ने बनारसवासियों के लिए काशी द्वार से सीधे बाबा के चौखट तक जाने का रास्ता खोल दिया है, जिससे काशीवासी हर्षित हैं। धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि काशीवासियों के लिए प्रातः 4:15 बजे से रात्रि 10:45 बजे तक (मंदिर खुलने के 15 मिनट बाद से मंदिर बंद होने के 15 मिनट पूर्व तक) 4-बी को ₹काशी द्वार₹ से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा विशेष तिथियों एवं पर्व दिवसों पर लागू नहीं होगी। इस विस्तारित व्यवस्था के प्रथम दिन 08 जुलाई 2026 को कुल 8,688 तथा 09 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक 5,196 काशीवासियों ने इस विशेष द्वार से जाकर बाबा का दर्शन किया।

इनका कहना है

भीड़ के कारण बाबा का दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी वालों की आवाज सुन ली है, जिससे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पहले की ही तरह जब भी चाहेंगे, आसानी से हो जाएगा।

संगीता गौरव
स्थानीय निवासी

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद श्रद्धालुओ की संख्या कई गुना बढ़ जाने से स्थानीय लोगों को दर्शन करने में कई घंटे लग जाते थे, जिससे कारोबार भी प्रभावित होता था। अब काशीवासियों के लिए यह सुविधा बाबा के वरदान से कम नहीं है।

रितेश राय
स्थानीय निवासी

रामनगर में 25 करोड़ से बनेगा अपना घर आश्रम

वाराणसी, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। निराश्रित, बेसहारा, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं जरूरतमंद लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यरत अपना घर आश्रम वाराणसी में अपनी सेवाओं का विस्तार करने जा रहा है। रामनगर क्षेत्र में आश्रम की दूसरी शाखा स्थापित की जाएगी, जिसके निर्माण पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। करीब दो बीघा भूमि पर बनने वाला यह अत्याधुनिक आश्रम एक हजार लोगों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा और पुनर्वास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। परियोजना के भूमि पूजन एवं शिलान्यास के लिए आश्रम के संस्थापक एवं मुख्य ट्रस्टी डॉ. के. निरंजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण दिया है। बुधवार को वाराणसी प्रवास के दौरान डॉ. के. निरंजन ने सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की।

होमगार्ड परिवार के स्वास्थ्य-सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील : धर्मवीर प्रजापति

लखनऊ, 09 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने गुरूवार को होमगार्ड्स मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति, सेवा की गुणवत्ता एवं जनोपयोगी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही आगामी 12 जुलाई के बृहद पौधरोपण अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

थाना चौकी न्याय का पहला मंदिर...खाकी पर जनता की जिम्मेदारी

वेब वार्ता, कानपुर। खाकी वर्दी और थाना न्याय का पहला मंदिर माना जाता है जहां सबसे पहले सुनवाई की उम्मीद लेकर पीड़ित पहुंचता है ऐसे में खाकी को जिम्मेदारी बेहद संजीदगी से निभानी चाहिये। महिला अपराधों में एक महिला के लिये पुलिसकर्मी की अहमियत ठीक उसी तरह हो जाती है जैसे परिवार में किसी बड़े के होने की होती है ..यह बात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहातकर ने ने कही राघवेंद्र स्वरूप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑडिटोरियम में आयोग द्वारा आयोजित शक्ति और सुरक्षा: एडवांसिंग जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग विषय पर दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के पहले दिन पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ का पुलिस प्रशासन महिलाओं को धरातल पर राहत देने के लिए पूरा सहयोग कर रहा है।

संबोधन के दौरान अध्यक्ष ने एक शहर के पुराने मामले का उदाहरण देते हुए पुलिस की लापरवाही को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, लेकिन पुलिस को चार दिन तक इसकी भनक ही नहीं लगी। जब पता चला, तब भी पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई में इतनी व्यस्त रही कि कानूनी नियमों को ही भूल गई। कानून के मुताबिक पीड़ित नाबालिग बच्ची को तुरंत महिला बाल कल्याण समिति के सामने हाजिर करना पुलिस की पहली जिम्मेदारी थी, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। कई बार महिलाएँ शिकायत लेकर आती हैं कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, चार-चार घंटे थाने में बिठाकर रखती है या रोज बुलाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करती। इस पर वे हंसी-मजाक में पीड़िता से पूछती हैं कि उनकी शिकायत प्रताड़ित करने वाले परिवार के खिलाफ है या पुलिस के खिलाफ ?तब महिला कहती है,कि शिकायत तो अपनों के ही खिलाफ है, लेकिन पुलिस को मदद करनी चाहिए थी। अध्यक्ष ने अधिकारियों का पक्ष लेते हुए यह भी साफ किया कि वे पुलिस को दोष नहीं दे रही हैं। क्योंकि कई मामलों में पुलिस बच्चों, परिवार और सही गलत का अनुभव करने के बाद फैसला लेती है।

हरदोई में बड़ा हादसा: शारदा नहर में डूबी तीन किशोरियाँ

दो को स्थानीय युवक ने बचाया, एक की तलाश में एनडीआरएफ का अभियान जारी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिले के कछौना थाना क्षेत्र के ग्राम समसपुर में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। धान की रोपाई के बाद शारदा नहर पर हाथ-पैर धोने गई तीन किशोरियां अचानक पैर फिसलने से नहर के तेज बहाव में बह गईं। मौके पर मौजूद एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर दो किशोरियों को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन 12 वर्षीय शिवांशी तेज बहाव में लापता हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, तहसील प्रशासन और बाद में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक खोज एवं बचाव अभियान जारी रहा।

जानकारी के अनुसार ग्राम समसपुर निवासी

कन्हैयालाल की पुत्रियां शिवांशी (12 वर्ष) और शिवानी (14 वर्ष) तथा गांव के ही मनोज की पुत्री नैंसी (13 वर्ष) अन्य बच्चों के साथ खेत में धान की रोपाई कर रही थीं। काम पूरा होने के बाद सभी बच्चे शारदा नहर पर हाथ-पैर धोने पहुंचे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और तीनों गहरे पानी में चली गईं। नहर में पानी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण वे खुद को संभाल नहीं सकीं और डूबने लगीं। बच्चियों की चीख-पुकार सुनकर पास में जानवर चरा रहे सुनील राठौर तुरंत नहर में कूद पड़े। उन्होंने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए शिवानी और नैंसी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण शिवांशी तक नहीं पहुंच सके। देखते ही देखते वह पानी में लापता हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। बेटी के लापता होने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112, कछौना पुलिस, फायर ब्रिगेड, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन को सूचना दी।

साइबर अपराधियों पर हरदोई पुलिस का बड़ा प्रहार, 25 शातिर गिरफ्तार

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जनपद में साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हरदोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी से जुड़े 25 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर सेल, सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की संयुक्त टीमों ने साइबर हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर यह सफलता हासिल की। कार्रवाई के दौरान थाना पाली से सात, सवायजपुर से पांच, कासिमपुर से नौ, पचदेवरा से दो, संडीला से एक तथा कोतवाली

शहर से एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। वहीं, कोतवाली शहर क्षेत्र से दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में सौरभ सिंह, संजीव उर्फ संजीत, रमाकांत, अंकित, अरुण कुमार, सचिन, अरविन्द, दुर्गेश चौहान, कृष्ण मुरारी उर्फ मुरारी, अंकित, राधा सिंह, मंजीत उर्फ नीलू, शलभ वाजपेयी, विजय पाल, रामकिशोर, प्रेमलता, सर्वेश, राजकुमार, रवि, अरुण, हरीशचन्द्र, सुलमत, धीरिश गोस्वामी, आरती सिंह तथा योगेश शामिल हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), धारा 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

जांच के दौरान थाना संडीला से संबंधित एक अभियुक्त के म्यूल बैंक खाते में मौजूद 40 लाख 75 हजार रुपये की संदिग्ध धनराशि पर तत्काल रोक लगवा दी गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह राशि साइबर ठगी से अर्जित होने की आशंका है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क, सहयोगियों तथा साइबर अपराध से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही बैंक खातों और आर्थिक लेन-देन की भी गहन पड़ताल की जा रही है। यदि चाहें तो इसे और अधिक अखबारी शैली में उपशीर्षक, बॉक्स आइटम और नाम-पता सहित भी तैयार किया जा सकता है।

...या निकटतम पुलिस थाने में सूचना दें

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में सक्रिय साइबर गिरोहों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, साइबर सेल, सर्विलांस टीम तथा संबंधित थाना प्रभारियों की संयुक्त टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक अथवा लालच देने वाले ऑनलाइन प्रस्तावों के झांसे में न आएं और साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या निकटतम पुलिस थाने में सूचना दें।

बरखेड़ा में वृक्ष भंडारा, 12 प्रजातियों के पौधे बांटकर हरित भविष्य का दिया संदेश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। वृहद वृक्षारोपण अभियान-2026 के अंतर्गत गुरुवार को विकासखंड बावन की ग्राम पंचायत बरखेड़ा में वृक्ष भंडारा का आयोजन किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती नेहा ब्याडवाल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान आम, अमरूद, बरगद, कटहल, पीपल, सहजन समेत 12 प्रजातियों के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना तथा पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ना रहा। पौधे प्राप्त करने वाले ग्रामीणों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रोपित करने और नियमित देखभाल कर वृक्ष के रूप में विकसित करने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि पौधारोपण तभी सार्थक

होगा, जब लगाए गए पौधों का संरक्षण भी पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती नेहा ब्याडवाल ने कहा कि आज का वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य में किया गया सामाजिक निवेश है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और लगातार घटते हरित क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान करते हुए लोगों से अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित रखने की अपील की।

अभियान के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवन, बरखेड़ा के समक्ष सहजन का पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पौधे लगाकर हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन तथा सतत विकास के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी बावन डॉ. राम प्रकाश, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) डॉ. प्रदीप कुमार, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने तथा अधिकाधिक पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प दोहराया।

महत्वपूर्ण ख़बर

मोंगला पोर्ट पर चीन का नया वॉच टावर

■ नई दिल्ली। बांग्लादेश ने हाल ही में अपने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन तैयार करने के लिए चीन के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। भारत के लिए बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट सामरिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत के पूर्वी तट के उत्तरी सिरे के बेहद करीब है। इसकारण बांग्लादेश और चीन की जुगलबंदी ने सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह समझौता भारत के लिए झटका है, क्योंकि मोंगला बंदरगाह के पास इकोनॉमिक जोन करने का काम पहले भारत को मिलने वाला था, लेकिन अब परियोजना चीन को सौंप दी गई है। चीन का इस इलाके में पहुंचना भारत की सुरक्षा के लि बड़ी चुनौती बन सकता है। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, जो बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्री और स्थलीय सीमा के करीब है। मोंगला से कोलकाता की जमीनी दूरी मात्र 188 किलोमीटर है, जबकि समुद्री मार्ग करीब 515 किलोमीटर का है।

ईरान का डर: कतर का जेट छोड़ पुराने एयरफोर्स वन से भरी उड़ान

अंकारा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन से वापसी के दौरान अपने विमान को बीच रास्ते में ही बदल लिया। उन्होंने कतर द्वारा उपहार में मिले नए बोइंग 747-8 जेट को छोड़कर अपने पुराने एयरफोर्स वन से उड़ान भरी। ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में एक संक्षिप्त ठहराव के बाद विमान बदलने के इस फैसले ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए सैन्य संघर्ष के बाद, यूएस सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति ट्रंप को विमान बदलने की सलाह दी थी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम किसी विशेष खतरे की प्रतिक्रिया के बजाय, एहतियात के तौर पर उठाया गया था, क्योंकि कतर से मिले नए विमान में अभी तक वे सभी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ स्थापित नहीं की गई थीं जो मौजूदा एयरफोर्स वन बेड़े में मौजूद हैं।

हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया कि नया विमान असुरक्षित है। व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने स्पष्ट किया कि नया जेट उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से लैस है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ध्यान भटकाने और गुमराह करने समेत अपने हर उपलब्ध उपकरण का इस्तेमाल करता है। खुद ट्रंप ने भी विमान बदलने के पीछे सुरक्षा चिंताओं की बात को खारिज कर दिया। ब्रिटेन से रवाना होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मुझ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर वन हूं। ट्रंप ने बताया कि ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में रुकने का असली मकसद वहां तैनात अमेरिकी सैन्यकर्मियों को नया विमान दिखाना था। उन्होंने नए विमान को बिल्कुल नया और शानदार बताते हुए सैन्यकर्मियों के साथ इसकी तस्वीरें भी साझा कीं और कहा कि वे लोग इसे देखकर काफी उत्साहित थे। पुरानी एयरफोर्स वन से सफर करने के पीछे ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करने के लिए ऐसा किया है। इस यात्रा के दौरान, पुरानी एयरफोर्स वन में सफर कर रहे पत्रकारों को फ्लाइट में खिड़कियों के ब्लाइंड्स (पर्दे) बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया था। ट्रंप ने बताया कि यह पाबंदी उनके निजी कंपार्टमेंट पर लागू नहीं थी।

उन्होंने ईरान की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कहा कि शायद ऐसा यहां मौजूद स्लीजबैग्स की वजह से किया गया हो। विमान बदलने का यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिका ने तेहरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए ईरानी ठिकानों पर नए सिरे से हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर है और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

ईरान पर अमेरिका की लगातार दूसरे दिन बमबारी

वॉशिंगटन। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मालवाहक जहाजों पर हुए हमलों के प्रतिशोध में अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भारी बमबारी की है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं तो इसके बहुत बुरे अंजाम होंगे। गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया, यह ईरान द्वारा कल मालवाहक जहाजों पर किए गए हमलों के प्रतिशोध में की गई कार्रवाई है। अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो अंजाम बहुत बुरा होगा! उनकी यह चेतावनी अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा ईरान के खिलाफ हवाई हमले शुरू करने के तुरंत बाद आई है।

अमेरिकी सेना ने इन हमलों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेहरान की अनुचित आक्रामकता का करारा जवाब बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, कमांडर इन चीफ यानी कि राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की ईरान की क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए हैं। कमांड ने आगे जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे जहाजों और उनके क्रू सदस्यों के खिलाफ की गई आक्रामकता के लिए सीधे तौर पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। यह सैन्य कार्रवाई ओमान के तट के पास कई मर्चेंट जहाजों को निशाना बनाए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई है। बुधवार को हुए पहले दौर के हमलों के बाद, गुरुवार को लगातार दूसरे दिन अमेरिकी युद्धक विमानों और मिसाइलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों और बंदरगाह सुविधाओं को निशाना बनाया।

पाकिस्तानी विमान दुर्घटना

मलबा मिला, पांच क्रू सदस्य लापता

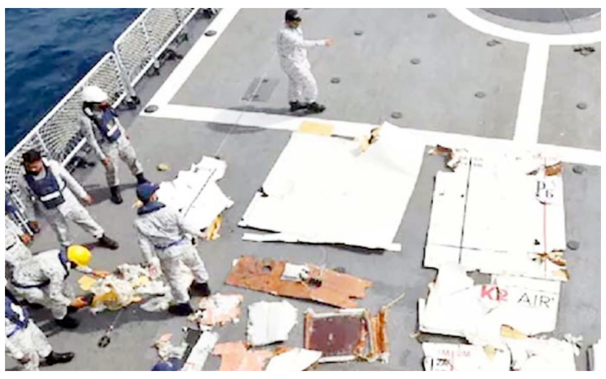

कराची। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से पाकिस्तान के कराची जा रहा के2 एयरवेज का एक बोइंग 737 कार्गो विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान का मलबा बुधवार को बरामद कर लिया गया है, हालांकि इसमें सवार पांच क्रू सदस्य अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के बाद लापता हुए इस विमान का मलबा करीब 12 घंटे के सघन तलाशी अभियान के बाद ओमार्रा बंदरगाह से लगभग 53 नॉटिकल मील दक्षिण में मिला। यह घटना मंगलवार शाम को हुई जब विमान ने शारजाह से उड़ान भरी थी।

हादसे से ठीक पहले विमान के पायलटों ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी थी। रडार डेटा से पता चलता है कि विमान ने अपनी दिशा में अचानक एक बड़ा बदलाव किया और फिर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। स्थानीय समयानुसार मंगलवार रात लगभग 9:21 बजे, कराची से लगभग 155 नॉटिकल मील पश्चिम में, विमान का रेडियो और रडार से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। इस गंभीर दुर्घटना की सूचना मिलते ही पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और विभिन्न नागरिक बचाव एजेंसियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अरब सागर में चलाए जा रहे इस अभियान में पाकिस्तान नेवी के युद्धपोत पीएनएस जुल्फिकार, नेवल सर्विलांस एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों के साथ-साथ कई मर्चेंट जहाजों को भी तैनात किया गया है, ताकि लापता क्रू सदस्यों का पता लगाया जा सके।

के2 एयरवेज ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी पांच क्रू सदस्यों – कैप्टन मुहम्मद रिजवान इदरिस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल जतोई, फ्लाइट इंजीनियर मुहम्मद हामिद, फ्लाइट इंजीनियर मुहम्मद आरिफ सिद्दीकी और एयरक्राफ्ट लोडर मुहम्मद तौफीक खान – का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एयरलाइन ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है और अपने साथियों की सुरक्षित वापसी के लिए निरंतर प्रार्थना करने की बात कही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और लापता क्रू मेंबर्स के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बचाव अभियान में तेजी लाने और हर संभव संसाधन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं हालांकि विमान के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की शुरूआती रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्घटना की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर एआरवाई न्यूज से बात करते हुए एविएशन एनालिस्ट इमरान असलम ने बताया कि विमान के इंजन फेल होने की स्थिति में भी वह आमतौर पर हवा में ग्लाइड करता है, न कि इतनी तेजी से नीचे गिरता है। दुर्घटना के सटीक कारणों का पता अब बरामद मलबे की विस्तृत फॉरेंसिक जांच के बाद ही चल पाएगा।

एच-1बी वीजा फजीवाड़े पर अमेरिका की बड़ी स्ट्राइक

भारत की दिग्गज कंपनी पर लटकी तलवार

वॉशिंगटन। अमेरिका ने एच-1बी और पर्म वर्क वीजा से जुड़े कथित धोखाधड़ी के खिलाफ एक व्यापक जांच अभियान शुरू किया है, जिससे भारतीय आईटी उद्योग की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट समेत कई बड़ी कंपनियां जांच के दायरे में आ गई हैं।

अमेरिकी श्रम विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बड़े फजीवाड़े की पुष्टि की है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टास्क फोर्स टू एलिमिनेट फ्रॉड कर रही है। यह कार्रवाई अमेरिका में वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक कड़ा कदम मानी जा रही है। श्रम विभाग के तहत काम करने वाले ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ने इस बड़े स्तर के फजीवाड़े का पदार्फाश किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, कई नियोक्ताओं और लेबर ब्रोकर्स ने मिलकर वीजा के लिए फर्जी आवेदन जमा किए। इसके अलावा, विदेशी कामगारों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, उनसे जबरन कम वेतन पर काम कराया गया और उनके मेहनताने में अवैध कटौतियां की गईं।

इस धोखाधड़ी के कारण कम मजदूरी वाले विदेशी कर्मचारियों से अमेरिकी बाजार को भर दिया गया, जिसका सीधा नुकसान अमेरिकी कामगारों को हुआ और उनकी नौकरियां छिन गईं। यह उन श्रम कार्यक्रमों की साख को भी कमजोर करता है, जिन्हें देश में वास्तविक श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था, न कि भ्रष्ट लोगों की जेब भरने के लिए। एक बातचीत के दौरान श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथोनी डी एस्पोसिटो का कहना था कि इस कार्रवाई की गंभीरता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया, हमने इस मामले में पहले ही दर्जनों समन जारी कर दिए हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जांच में मिले हर एक सुराग की तह तक जाएं। आईटी दिग्गज कॉग्निजेंट का विशेष उल्लेख करते हुए एस्पोसिटो ने कहा, हमारे पास ऐसे व्हिसलब्लोअर्स मौजूद हैं जो कॉग्निजेंट जैसी कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बयान में स्पष्ट किया है कि वे ऐसे जालसाजों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो विदेशी गेस्ट वर्कर वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को बढ़ावा देते हैं।

...और देश की श्रम नीतियाँ सुरक्षित रहें

एजेंसी का साफ कहना है कि वह उन सभी साजिशों को जड़ से खत्म करेगी जो मजबूर मजदूरों का शोषण करते हैं और अमेरिकी नागरिकों के हक की नौकरियां छीनते हैं। यह जांच अभियान उन कंपनियों और व्यक्तियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो अमेरिकी वीजा कानूनों का उल्लंघन कर अनुचित लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, और यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी श्रमिकों के अधिकार और देश की श्रम नीतियां सुरक्षित रहें।

एएमसीए: स्वदेशी टाइटेनियम से बनेगा भारत का महाबली सुपर फाइटर, एफ-35 को देगा चुनौती

नई दिल्ली। भारत का बहुप्रतीक्षित सुपर लड़ाकू विमान, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्रॉफ्ट (एएमसीए), परंपरागत फौलादी सामग्री के बजाय अमेरिकी एफ-35 फाइटर जेट की तर्ज पर बेहद हल्के टाइटेनियम धातु का उपयोग करेगा। यह नई बनावट विमान की क्षमता में असाधारण वृद्धि करेगी और अमेरिकी एफ-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के शक्तिशाली विमानों से टक्कर लेने में सक्षम बनाएगी। टाइटेनियम की यह संरचना एएमसीए को न केवल तीव्र गति से उड़ान भरने, बल्कि दुश्मन पर कहर बनकर टूटने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करेगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एएमसीए की बॉडी के साथ-साथ इसका लैंडिंग गियर भी टाइटेनियम का बना होगा, जो विमान के समग्र वजन को कम रखते हुए उसकी स्टील्थ (रडार से बचने की) तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह हल्का और मजबूत धातु जंग रहित होता है, जो इस लंबी सेवा अवधि के लिए उपयुक्त बनाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उसकी डिफेंस मेटलर्जिकन रिसर्च लेबोरेटरी (डीएमआरएल) ने स्वदेशी बीटा टाइटेनियम टीआई 10 वी-2एफई-3एआई विकसित किया है, जिससे विमान का वजन 18-25 टन के अनुमानित लक्ष्य तक रखने में मदद मिलेगी और इसकी मारक क्षमता बढ़ेगी। एएमसीए के डिजाइन में केवल कम रडार सिग्नेचर पर ही नहीं, बल्कि आसान रखरखाव पर भी समान जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी एफ-35 जैसे पश्चिमी देशों के स्टील्थ जेट्स को अपनी नाजुक रडार-अवशोषित कोटिंग्स, जटिल सॉफ्टवेयर बग और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के कारण खराब मिशन तैयारी का सामना करना पड़ा है।

महाराष्ट्र में दोहरी मार: झमाझम बारिश के बीच लगे भूकंप के 4 झटके

मुंबई। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बीते गुरुवार को मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों में भूकंप के चार हल्के झटके महसूस किए गए, जिसने आधी रात को धरती को कंपा दिया। एक अधिकारी ने बताया कि ये झटके रात 1.37 बजे से 3.23 बजे के बीच आए और रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.6 से 4.6 के बीच मापी गई। जिला आपातकालीन केंद्र को रात 01:37, 02:15, 02:17 और 03:23 बजे इन झटकों की सूचना मिली। पहले झटके की तीव्रता 4.6, दूसरे की 3.6, तीसरे की 3.9 और चौथे की 4.1 मापी गई।

भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के वसमत तालुका में शिरली गांव में स्थित था। राहत की बात यह रही कि जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली, जबकि इन झटकों के आने के समय ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे।

हिंगोली, नांदेड़ और परभणी के कई निवासियों ने इन तीव्र कंपनों को महसूस किया। पहले झटके का केंद्र हिंगोली जिले के वसमत तालुका में पांगरा शिंदे गांव के दक्षिण में शिरली गांव के पास था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई। बाद के दो झटकों के केंद्र पांगरा शिंदे गांव के उत्तर-पश्चिम में स्थित ककड़धाबा गांव के पास थे और वे भी 10 किलोमीटर की गहराई पर आए। पिछले छह वर्षों में, हिंगोली जिले के औंधा नागनाथ, कलमनुरी और वसमत तालुका में 37 से अधिक हल्के भूकंप दर्ज किए गए हैं, लेकिन एक ही रात में चार झटके आना यह पहली बार दर्ज किया गया मामला है, जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी की बाहरी परत में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने या हिलने-डुलने से आते हैं। हमारी पृथ्वी की क्रस्ट कई विशाल प्लेट्स में विभाजित है जो मैग्मा की ऊपरी परत पर तैरती रहती हैं। ये प्लेटें लगातार धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर या पास आती रहती हैं। जब इन प्लेटों की सीमाओं पर घर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है और वे अचानक फिसलती हैं, तो भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा की लहरें पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा करती हैं, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। इसके अलावा, ज्वालामुखी गतिविधि, बड़े बांधों का निर्माण या खदानों में किए जाने वाले विस्फोट जैसी मानवीय गतिविधियां भी छोटे भूकंपों का कारण बन सकती हैं।

भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है और यह एक प्राकृतिक आपदा है जो जान-माल की भारी क्षति कर सकती है, इसलिए भूकंप-प्रतिरोधी भवन निर्माण और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत कई राज्यों में बरस रहा बारिश का कहर

नई दिल्ली। भारत में राहत की बारिश लाने वाला मॉनसून का मौसम अब विनाशकारी रूप ले चुका है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कों से लेकर रेल पटरियों तक सब कुछ पानी में डूब गया है, और आने वाले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं हैं। परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जबकि कई स्थानों पर बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने हाहाकार मचा रखा है।महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश ने स्थिति गंभीर कर दी है। मुंबई में बुधवार को लोकल ट्रेनें 25 से 30 मिनट की देरी से चलीं, जबकि गुजरात और पुणे की ओर जाने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। गुजरात जाने वाली 39 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाली 46 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। भोर घाट क्षेत्र में हुए भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे मार्ग पर रेल परिचालन अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है और कई प्राचीन मंदिर जलमग्न हो गए हैं।

गर्भवती को लेकर जा रही एंबुलेंस फंसी

महाराष्ट्र के पालघर जिले के बाढ़ग्रस्त हनुमानपाड़ा गांव में सड़कें डूब जाने से एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद ग्रामीणों ने घर के दरवाजे को स्ट्रेचर बनाकर प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला को सीने तक भरे पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी- चिंचवड़ में बुधवार को भारी बारिश के दौरान कचरे का विशाल ढेर तीन मंजिला इमारत पर गिरने से वह ढह गई। हादसे में 16 लोग दब गए, जिनमें से सात को बचा लिया गया, जबकि राहत और बचाव अभियान जारी है।

सूरत में 3,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया

सूरत में 358 मिमी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जहां 3,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिले में पिछले कुछ दिनों में बारिश से संबंधित घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में मंगलवार देर रात तुलसी और विहार झीलें ओवरफ्लो हो गईं, जो शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली सात प्रमुख झीलों में से हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में वसई रोड से आगे उपनगरीय रेल सेवाएं बंद होने के बाद यात्रियों को आधी रात को मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में जलमग्न पटरियों पर पैदल चलते देखा गया।

हिमाचल और राजस्थान में भी बुरा हाल

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भी बारिश जारी रही और शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के कुछ हिस्सों में अचानक आई बाढ़ से सड़क संपर्क बाधित हो गया। जलस्तर बढ़ने से गानवी खड्ड नाले पर बना एक अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दोनों तरफ का संपर्क टूट गया। राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने से अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा और अन्य जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ; कई शहरों में सड़कें और बाजार जलमग्न हो गए। कोटा जिले के रामगंजमंडी में सबसे अधिक 10 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से बात कर भारी बारिश की स्थिति की समीक्षा की और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। शाह ने वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना पर दुख व्यक्त किया। वायनाड में सुरंग मार्ग निर्माण स्थल पर भूस्खलन के दूसरे दिन बुधवार को लापता पांच श्रमिकों की तलाश जारी रही; हादसे में मारे गए तीन श्रमिकों के शवों को कंपनी को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात धीमा पड़ गया। आईएमडी ने गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ह्यरेडह्न और ह्यऑरेंजह्न अलर्ट जारी किया है। सदर बाजार, नसीरपुर, ग्रेटर कैलाश, बदरपुर, तेलीवाड़ा, महावीर बाजार, स्वरूप नगर और कुशक रोड सहित कई इलाके जलमग्न रहे, जहां लोगों को घुटनों तक पानी में चलकर निकलना पड़ा।

भारत को रूस से हथियार खरीदने में मिलेगी छूट? तुर्की से जुड़ा पूरा मामला

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर लगे सीएएटीएसए प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया है, यह ऐलान भारत के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। भारत दशकों से अपने गहरे मित्र रूस से हथियार खरीदता रहा है, और भारतीय सेना के करीब 70 फीसदी हथियार रूसी मूल के हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से हथियार दोस्ती पर अमेरिका के सीएएटीएसए प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा है।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में तुर्की को रूस से एस-400 वायुरक्षा प्रणाली खरीदने के बाद सीएएटीएसए (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन्स एक्ट) प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, नाटो सदस्य तुर्की को अमेरिका के एफ-35 फाइटर जेट कार्यक्रम से भी बाहर किया था। अमेरिका को यह डर था कि एस-400 की सक्रियता से अमेरिकी एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट की गुप्त कमजोरियां उजागर हो सकती हैं।

नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ बातचीत में ट्रंप ने घोषणा की कि वे तुर्की को अमेरिकी ब्लैकलिस्ट से निकालने पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने एर्दोगन को अपना मित्र बताकर कहा, हम प्रतिबंधों को खत्म करने जा रहे हैं। अब प्रतिबंधों को खत्म करने का समय आ गया है। हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं। यह कानून मूल रूप से 2017 में रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को निशाना बनाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन रूस से एस-400 की खरीद के बाद तुर्की को भी इसमें शामिल किया था।

ताजा खबर

संक्षिप्त

सशक्त संगठन ही जनसेवा की सबसे बड़ी शक्ति है: सीएम विष्णुदेव साय

कवर्धा। सीएम विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले में नवीन भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, सशक्त संगठन ही जनसेवा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह नवीन पार्टी कार्यालय संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति देने, कार्यकर्ताओं को सशक्त मंच उपलब्ध कराने के साथ ही जनसेवा के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। यह कार्यालय हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिनके अथक परिश्रम, समर्पण और सेवा भाव ने संगठन को निरंतर नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। संगठन की यही शक्ति विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय , प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन , राजनांदगाँव लोकसभा सांसद संतोष पांडे, विधायक सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या मे कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में नंबर-1 बना बोधघाट थाना, केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिला राष्ट्रीय सम्मान

जगदलपुर। बस्तर जिले के बोधघाट थाने ने पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एनुअल पुलिस स्टेशन रैंकिंग-2025 में बोधघाट थाना प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। अपराध नियंत्रण, एनडीपीएस मामलों में प्रभावी कार्रवाई, कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट, इनोवेशन इन पुलिसिंग और एक्सीलेंस इन पुलिसिंग जैसे अहम मानकों पर शानदार प्रदर्शन के आधार पर यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बोधघाट पुलिस स्टेशन का चयन किया गया। यह उपलब्धि पूरे बस्तर पुलिस के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस्तर रेंज और बस्तर जिले के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी थाने को पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। तत्कालीन थाना प्रभारी लीलाधर राठौड़ के नेतृत्व में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और वर्तमान थाना प्रभारी तामेश्वर चौहान सहित पूरे पुलिस स्टाफ की टीमवर्क ने इस सफलता की मजबूत नींव रखी। अधिकारियों ने इसे बस्तर पुलिस की प्रोफेशनल, जन-केंद्रित और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली का प्रमाण बताया है।

वीबी शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, संसद की समिति की मुहर

रायपुर। सांसद एवं समिति सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को नई दिल्ली में संसद परिसर में आयोजित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधेयक से जुड़े विभिन्न नीतिगत बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और अपने सुझाव दिए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बैठक में विधेयक के सभी प्रावधानों पर बिन्दुवार गहन विचार विमर्श कर विधेयक को अंतिम रूप दिया गया। संसद के आगामी मानसून सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगायह विधेयक देश में उच्च शिक्षा (Higher Education) के स्तर को न सिर्फ नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। विधेयक वास्तव में देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को केवल डिग्री बांटने के पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकालकर वैश्विक मानकों, नवाचार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न को धरातल पर उतारने के लिए तैयार किया गया यह विधेयक, उच्च शिक्षा के पूरे ढांचे को पुनर्गठित करने की बात करता है।

तीजन बाई के नाम पर दिया जाएगा राज्य अलंकरण पुरस्कार, संस्कृति मंत्री ने की घोषणा

रायपुर. छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पंडवानी की महान लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की स्मृति को हमेशा के लिए संजोने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

रायपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का योगदान केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर है और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि पंडवानी कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलाकारों को अब हर वर्ष %डॉ. तीजन बाई राज्य अलंकरण सम्मान% से सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोककला के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर संस्कृति मंत्री ने डॉ. तीजन बाई के परिजनों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार कलाकारों और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

डॉ. तीजन बाई के पैतृक गांव गनियारी को कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।

यहां लोककला, पंडवानी और पारंपरिक संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यह स्थान कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन सके। इसके अलावा, डॉ. तीजन बाई की प्रस्तुतियों का अभिन्न हिस्सा रहा उनका ऐतिहासिक तंबूरा अब रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। इसे आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उनकी कला और जीवन यात्रा को नजदीक से जानने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपने अद्वितीय गायन और अभिनय से पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया।

राज्य सरकार की ये पहलें उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगी।

अंतर विभागीय समितियों के गठन में नहीं चलेगी मनमर्जी

जीएडी से अनुमति जरूरी, कुछ शर्तें भी तय किए गए

रायपुर। साप्रवि ने सचिवों की अंतर विभागीय समितियों के गठन को लेकर न?ए निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक अब विभाग अपनी मन मर्जी से ये समितियां गठित नहीं कर पाएंगे। उन्हें साप्रवि से अनुमति लेकर ही करना होगा। गठन भी जीएडी ही करेगा।

सचिव अविनाश चंपावत ने आज सभी एसीएस पीएस और सचिवों को पत्र भेजकर इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा अपनी विभागीय योजनाओं /परियोजनाओं के क्रियान्वयन और अंतर्विभागीय समन्वय हेतु अधिकारी स्तरीय अंतर्विभागीय समिति के गठन के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किए जाते हैं। प्राय: यह देखा गया है कि इन प्रस्तावों में समिति के गठन का औचित्य, कार्यक्षेत्र, सदस्यों के विभाग का नाम तथा पदनाम स्पष्ट नहीं होती, जिससे न केवल नस्ती निस्तारण किये जाने में अनावश्यक विलंब होता है, बल्कि प्रशासनिक समन्वय में भी कठिनाई आती है। एकरूपता की दृष्टि से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय समितियों के गठन के औपचारिक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही जारी किए जाएंगे। विभाग ऐसी समितियों के गठन हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर, प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को समिति गठन के आदेश प्रसारित करने के लिए भेजेंगे।

शासन द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित और तीव्र बनाने के उद्देश्य से यह निर्देशित किया है।

गठन के लिए निम्न बिन्दुओं का पालन अनिवार्य

केवल राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति गठन के प्रस्ताव इस विभाग को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित किया जाए, जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी नामित हो। संभाग एवं जिला स्तरीय समिति गठन संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे। द्वद्वद्व. राज्य स्तरीय समिति की संरचना और कार्यक्षेत्र पर संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाए। गठित की जाने वाली समिति में यदि किसी अशासकीय सदस्य को शामिल किया जाना है तो उसके मनोनयन के पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जावे। माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बिना समिति में अशासकीय सदस्यों का मनोनयन छत्तीसगढ़ शासन के कार्यपालिक नियम के भाग-चार के बिन्दु क्रमांक-एक (घघ) के विपरीत है। ई-ऑफिस नस्ती में आदेश प्रारूप संलग्न किया जावे जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सदस्य विभागों के नाम (पदनाम सहित) का स्पष्ट उल्लेख हो। समिति का गठन क्यों आवश्यक है एवं विभागीय कार्यदल गठित कर यह कार्य क्यों संभव नहीं है, इसका स्पष्ट उल्लेख हो तथा समिति के विशिष्ट कार्य, अधिकार और निर्णय लेने की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। GENCOR-35010/2119/2026-GAD-5 1/489387/2026 बोर्ड/निगम/मंडल/प्राधिकरण के गठन हेतु प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित न किया जाए। जांच समिति एवं क्रय/वित्तीय संबंधी समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा, उक्त के संबंध में प्रशासकीय विभाग स्वयं प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर समिति गठन करेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया जाकर मुख्य सचिव जी के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन उपरान्त औपचारिक आदेश प्रसारित किया जाएगा।

एस.डी.जी. 2.0 बस्तर अंजोर से विकसित छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई गति : सीएम साय

मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. राज्य एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क 2.0 तथा मेटाडेटा हैंडबुक का भी विमोचन किया गया। साथ ही बस्तर संभाग के समावेशी, अभिसरण आधारित और मापनीय विकास के लिए तैयार की गई अभिनव पहल बस्तर अंजोर की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क शासन को साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि यह पहल %विकसित छत्तीसगढ़ ञ्2047% के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।नए एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य स्तर पर संकेतकों की संख्या 275 से बढ़ाकर 343 तथा जिला स्तर पर 82 से बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इससे विकास कार्यों की अधिक व्यापक, सटीक और वैज्ञानिक निगरानी संभव होगी। मेटाडेटा हैंडबुक में प्रत्येक संकेतक की गणना पद्धति एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मानकीकृत किया गया है, जिससे पूरे राज्य में डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने %बस्तर अंजोर% की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह अभिसरण (कन्वर्जेंस) आधारित विकास मॉडल है, जिसे बस्तर संभाग को देश का सर्वाधिक विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर अंजोर के 3+4 मॉडल के अंतर्गत जिला स्तर की तीन प्रमुख पहल - नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और स्वस्थ बस्तर - का अभिसरण चार प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास फ्रेमवर्क - एस.डी.जी. 2030, विकसित छत्तीसगढ़ @2047, आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम से किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास 2.0 लैंड टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

पात्र आवासहीन परिवारों को पक्का घर मिले यह सुनिश्चित हो

रायपुर. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रोजेक्ट के लिए भूमि के सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास 2.0 के लिए हितग्राही की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर सत्यापन करना एवं उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों में वर्तमान और भविष्य की आवासीय आवश्यकता का आंकलन कर कार्ययोजना बनाने कहा है। जिससे समय पर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जा सकें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनांतर्गत हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार आवास बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर.शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायगढ़ को डीएमएफ से 4.13 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व तथा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के विशेष प्रयासों से रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) द्वारा 4 करोड़ 13 लाख 82 हजार 400 रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जिले के ग्रामीण एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनसुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धरमजयगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा के निर्माण एवं उन्नयन कार्य के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पांच पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। ग्राम गोरपार एवं नंदगांव में 25 केएल सम्पवेल आधारित पेयजल व्यवस्था के लिए 6 लाख 47 हजार 700 रुपये-रुपये, ग्राम शहपुर में नलकूप खनन, रॉ-वॉटर पंप एवं पाइपलाइन विस्तार के लिए 9 लाख 94 हजार रुपये, ग्राम नवापारा के लिए 5 लाख 32 हजार रुपये तथा ग्राम पुसल्दा के लिए 8 लाख 45 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रमोशन, 61 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बड़ी पदोन्नति की गई है। पुलिस मुख्यालय (क्क्वक्त) नवा रायपुर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रदेश के 61 सब इंस्पेक्टर्स (उप निरीक्षकों) को इंस्पेक्टर (निरीक्षक) के पद पर प्रमोट किया गया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम के हस्ताक्षर से वर्ष 2026 की यह योग्यता सूची जारी की गई है।इस पदोन्नति सूची की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रमोट होने वाले अधिकांश सब इंस्पेक्टर वर्ष 2013 बैच के हैं। 12 अगस्त 2013 और उसके आस-पास नियुक्त हुए इन अधिकारियों को लंबे समय से इस प्रमोशन का इंतजार था। सूची में पहले स्थान पर सक्ती जिले के श्री चन्द्रप्रकाश कंवर का नाम है, वहीं गरियाबंद के मनीष यादव, बलौदाबाजार के प्रियेश जॉन और नारायणपुर के धीरेंद्र कुमार तिवारी समेत कुल 61 पुलिस अफसरों के नाम शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी

4 निगम समेत 15 निकायों के दिसंबर में चुनाव

रायपुर। भिलाई निगम में न?ई आयुक्त की नियुक्ति के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 निकायों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें 4 निगम,5 पालिका और 9 नगर पंचायत शामिल हैं। ये चुनाव दिसंबर में होंगे। सभी राजनीतिक दृष्टि से अहम निकाय हैं।

नवा रायपुर में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सिंह का कार्यकाल भी छः महीने के लिए बढ़ाया गया है। बैठक में प्रदेश की 15 नगरीय निकायों(जिनमें 4 नगरपालिक निगम, 5 नगरपालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है) के साथ ही दो नवगठित नगर पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों एवं शासन स्तर पर की जा रही आवश्यक कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रस्तावित हैं, उनमें नगर निगम बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा एवं रिसाली, नगरपालिका परिषद जामुल, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा एवं खैरागढ़ तथा नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ एवं भोपालपट्टनम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नवगठित नगर पंचायत तमनार एवं बड़ी करेली में भी आम निर्वाचन कराया जाएगा।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर संगीता ने वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 15 नगरीय निकायों में महापौर एवं अध्यक्ष पदों का आरक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा वार्ड पार्षदों के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। वहीं नवगठित नगर पंचायत तमनार में वार्ड आरक्षण तथा बड़ी करेली में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की कार्रवाई प्रगति पर है। विभाग द्वारा दो वार्ड पार्षद पदों पर आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक शासकीय प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पांच जिपं सीईओ बदले, रेमिजियुस एक्का को सुडा का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के तहत पांच जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (ष्टश्वह्र) का तबादला किया गया है। इसके अलावा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक रेमिजियुस एक्का को राज्य शहरी विकास अभिकरण (स्ष्ठ) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। आदेश के अनुसार, रेमिजियुस एक्का (भा.प्र.से. 2011) अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ स्ष्ठ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इसके अलावा निम्न अधिकारियों के तबादले किए गए हैं- गजेन्द्र सिंह ठाकुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी को उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग में पदस्थ किया गया है। प्रतीक जैन को जिला पंचायत बस्तर से जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। सुरुचि सिंह को जिला पंचायत राजनांदगांव से आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई पदस्थ किया गया है। जयंत नाहटा को जिला पंचायत दंतेवाड़ा से जिला पंचायत धमतरी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।

फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची आठ टीमें में चार रही हैं पूर्व विजेता

अटलांटा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में आठ टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं जिनके बीच शुक्रवार से मुकाबले होंगे। इनमें से चार टीमें विजेता रही हैं। विश्वकप में कुल 104 मैच खेले जाने हैं, जिनमें से 96 मुकाबले अब तक हुए हैं। वहीं 40 टीमें बाहर हो गयी हैं, और अब केवल 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें ही मुकाबले में बची हैं। इनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल 2 फाइनल में पहुँचेंगी और अंत में एक के नाम खिताब होगा। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली आठ टीमें हैं। फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड। इनमें से छह टीमें यूरोप की हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में फ्रांस का मुकाबला 10 जुलाई को देर रात 1:30 बजे मोरक्को से होगा। इसके बाद 11 जुलाई को देर रात 12:30 बजे स्पेन और बेल्जियम के बीच टक्कर होगी। 12 जुलाई को सुबह 2:30 बजे नॉर्वे इंग्लैंड से खेलेगी जबकि सुबह 6:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होना है। इन चार मुकाबलों के विजेता सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे।

क्वार्टर फाइनल में पहुंचीचार टीमें फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने पहले भी खिताब जीता है। वहीं मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। अर्जेंटीना ने 1978, 1986 और 2022 में तीन बार विश्व कप जीता है, वहीं फ्रांस ने 1998 और 2018 में दो बार यह गौरव हासिल किया है, जबकि इंग्लैंड (1966) और स्पेन (2010) ने एक-एक बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता था।

जहां तक अन्य चार टीमों की बात है। मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम आज तक विश्व कप फाइनल में नहीं पहुंची हैं। मोरक्को विश्व कप 2022 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। वहीं स्विट्जरलैंड चार बार 1934, 1938, 1954 और इस बार 2026 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। बेल्जियम ने 2018 फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया था। नार्वे की बात करें तो इसी बार वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। अब देखना होगा कि चार पूर्व विजेताओं में से कोई टीम खिताब जीतती है या किसी नई टीम को अवसर मिलता है।

वैभव विरोधी गेंदबाजों से सतर्क रहें : पठान

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। पठान का मानना है कि 15 वर्षीय इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। अपने करियर की शानदार शुरूआत के बाद, इस क्रिकेटर को अब विरोधी गेंदबाजों की रणनीतियों का सामना करने और उनसे पार पाने के लिए तैयार रहना होगा।

पठान ने इस बात पर जोर दिया कि वैभव का निडर और स्वाभाविक खेल बना रहना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लगातार और दीर्घकालिक सफलता हासिल करने के लिए विरोधी टीमों की रणनीतियों के हिसाब से खुद को ढालना अत्यंत आवश्यक है। पठान ने स्पष्ट किया, इसमें कोई शक नहीं कि वह एक खास प्रतिभा है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह गेंदबाजों की हर चाल का सामना करने के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार रहे। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे अगर आप इंग्लैंड में स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं, तो यह कोई बुरा विकल्प नहीं है क्योंकि वहां गेंद आमतौर पर ज्यादा टर्न नहीं होती। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपना संतुलन बनाए रखना होगा और गेंद से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना होगा, ताकि आप हर स्थिति में नियंत्रण बनाए रख सकें।

पठान ने इस युवा खिलाड़ी के दृढ़ इरादे और आत्मविश्वास की भरपूर तारीफ की। उन्होंने खुशी जताई कि वैभव ने अपने पहले कुछ अंतरराष्ट्रीय मैचों में, विशेष रूप से दूसरे और तीसरे टी20 में, अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल छोड़ने से परहेज नहीं किया। भले ही इन दोनों मैचों में वैभव ने क्रमश: 14 और 13 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 200 से अधिक रहा, जो उनके निडर रुख को दिखाता है। पठान ने कहा, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि वह अपना स्वाभाविक खेल खेलने से पीछे नहीं हटे और दबाव में भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो उनकी मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है।

बाबर आजम को फिर से टी20 कप्तान बना सकता है पीसीबी

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अनुभवी बल्लेबाज बाबार आजम को एक बार फिर टी20 में भी कप्तान बना सकता है। बाबर पहले भी इस प्रारुप में कप्तान रहे हैं और उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। हाल में जिस प्रकार से उन्हें टेस्ट में कप्तानी मिली है। उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब इस बल्लेबाज को आगामी मैचों से पहले टी20 टीम की कप्तानी फिर से सौंपी जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, पीसीबी राष्ट्रीय टीम के हाल के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा है। यदि इस निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो बाबर एक बार फिर सलमान अली आगा की जगह लेंगे, जो बदलाव के दौर में टीम की कमान संभाल रहे थे पर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है।

बोर्ड एक बार फिर देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी पर अपना भरोसा जता सकता है। हालांकि,

पीसीबी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है पर रिपोर्टों में कहा गया है कि बाबर का नाम सबसे आगे चल रहा है। पाकिस्तान को आगामी अंतरराष्ट्रीय मैचों और आईसीसी इवेंट्स के लिए तैयारी करनी है।

बाबर पहले भी तीनों प्रारुपों में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं और टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्हें अच्छी सफलता मिली थी। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 2021 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था और 2022 के संस्करण में उपविजेता रहा था। यह प्रदर्शन उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। इतना ही नहीं, अपने पिछले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के टी20 कप्तानों में उनका जीत का प्रतिशत भी सबसे बेहतरीन रहा था, जो उनकी प्रभावी रणनीतियों और टीम को एकजुट रखने की क्षमता को दशार्ता है। वह सफेद गेंद क्रिकेट में बाबर पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बने हुए हैं। माना जाता है कि उनका अनुभव, कुशल नेतृत्व क्षमता और कप्तानी की जटिल जरूरतों की गहरी समझ उन प्रमुख कारकों में शामिल हैं जो बोर्ड की इस सोच को प्रभावित कर रहे हैं।

प्रदर्शन के साथ ही फिटनेस भी जरुरी : मनप्रीत

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने कहा है टीम में जगह बनाये रखने के लिए प्रदर्शन के साथ ही फिटनेस पर भी ध्यान देना सबसे जरुरी है। मनप्रीत ने कहा कि फिटनेस बनी रहने के कारण ही वह भारत की ओर से सबसे अधिक मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे हैं। मनप्रीत ने खेल में अपनी सफलता का श्रेय अपने फिटनेस को दिया है। साथ ही कहा है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के कारण ही वह इतने लंबे समय तक वह देश के लिए खेल पाए हैं। इस खिलाड़ी ने कहा कि टीम में बने रहने के लिए उम्र और अनुभव पर ध्यान न देते हुए लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होता है। साथ ही कहा कि जैसे-जैसे मैचों की संख्या बढ़ती है फिटनेस भी बनाये रखनी होती है। अगर फिटनेस कमजोर पड़ती है तो टीम में जगह भी हाथ से निकल जाती है। मनप्रीत ने कहा, कोचिंग स्टाफ का भी हमेशा से यह कहना रहा है कि प्रदर्शन और चयन फिटनेस से जुड़े रहते हैं। इसलिए अगर आपको टीम में बने रहना है, तो आपको हर समय फिटनेस बनाये रखनी होगी। यहां तक कि ब्रेक के दौरान भी लापरवाही नहीं की जा सकती है।

उन्होंने कहा, जब भी मैं ब्रेक पर होता हूं या शिविर में होता हूं, तो मैं फिट रहने के लिए अपना रूटीन जारी रखता हूं। अगर मुझे भारतीय टीम के लिए खेलना है, तो मुझे अपने को पूरी तरह से फिट रखना होगा और अपनी फिटनेस के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने अपने डाइट का भी विशेष रुप से ध्यान रखा है।मनप्रीत ने कहा कि कुछ सालों में मैचों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में फिटनेस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब तक 413 मैच खेल चुके मनप्रीत ने 2011 में भारत के लिए डेब्यू किया था।

विश्वनाथ और चंद्रिका के नेतृत्व में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उतरेगी भारतीय टीम

नई दिल्ली

एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में स्वर्ण विजेता रही चंद्रिका भोरेश पुजारी की अगुवाई में भारतीय मुक्केबाजी दल शुक्रवार से इंडोनेशिया में शुरू होने वाली अंडर-23 और अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। भारतीय टीम में दोनों आयु वर्गों के लिए प्रतिभाशाली मुक्केबाज शामिल हैं, जिनसे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में उसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हैं।

इस चैंपियनशिप से भारतीय युवा मुक्केबाजों के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल को एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ साबित करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय शिविर में प्रशिक्षण हासिल किया है। जिससे उसका लक्ष्य एशियाई चैम्पियनशिप में पदक जीतना रहेगा। टीम में शामिल मुक्केबाज न केवल अपने लिए, बल्कि देश के लिए भी गौरव हासिल करने को उत्सुक हैं।

अंडर-23 पुरुष वर्ग में, 50 किग्रा भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ गंगा (55 किग्रा), सागर जाखड़ (60 किग्रा), वंशज (65 किग्रा), हितेश (70 किग्रा), नीरज (75 किग्रा), आर्यन मलिक (80 किग्रा), रॉकी चौधरी (85 किग्रा), हेमंत सांगवान (90 किग्रा) और इशान कटारिया (90 किग्रा) जैसे प्रतिभाशाली मुक्केबाज शामिल हैं। यह एक अनुभव और युवा

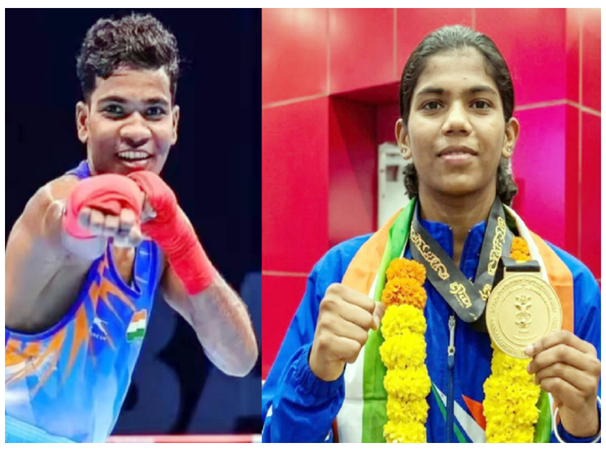

जोश का मिश्रण है, जो टीम को मजबूती प्रदान करता है।

वहीं महिला अंडर-23 टीम की अगुवाई निधि (48 किग्रा) और तनु (51 किग्रा) करेंगी। इस टीम में निशा (54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), निकिता चंद (60 किग्रा), काजल (65 किग्रा), शिवानी (70 किग्रा), मुस्कान (75 किग्रा), नैना (80 किग्रा) और प्रियंका (80 किग्रा) जैसी कई और प्रतिभाशाली मुक्केबाज भी हैं, जिनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ये सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं और अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं।

अंडर-19 महिला टीम विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप की स्वर्ण पदक विजेता चंद्रिका भोरेश पुजारी के नेतृत्व में रिंग में उतरेगी। उनके साथ गुंजन (48 किग्रा), चिरोम जॉयश्री देवी (54 किग्रा) और प्राची (57 किग्रा) सहित कई उभरती हुई युवा प्रतिभाएं शामिल हैं, जो अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने का लक्ष्य रखेंगी। यह टीम भविष्य के लिए भारतीय मुक्केबाजी की मजबूत नींव तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अंडर-19 पुरुष टीम में भी युवा प्रतिभाओं को भरपूर मौका मिला है, जिसमें लैरेनलाकपम अंबेडकर मैतेई (50 किग्रा), आदित्य (55 किग्रा) और सिकंदर (60 किग्रा) जैसे मुक्केबाज शामिल हैं। चयनकताओं को इन सभी खिलाड़ियों से टूनामेंट में प्रभावी प्रदर्शन और पदक जीतने की प्रबल उम्मीद है।

नई किया साइरोस ईवी जल्द होगी लॉन्च

नई दिल्ली। कार निमार्ता कंपनी किया इंडिया अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। अगले महीने किआ इंडिया कंपनी अपनी नई किया साइरोस ईवी को लॉन्च कर सकती है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और टाटा पंच ईवी के उच्च वेरिएंट्स से होने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले, किया साइरोस ईवी को एक बार फिर भारतीय सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा गया है। सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसका डिजाइन मौजूदा

पेट्रोल और डीजल मॉडल से काफी मिलता-जुलता रहेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए कुछ खास बदलाव किए जाएंगे। इन बदलावों में चार्जिंग पोर्ट को आगे बाईं तरफ व्हील आर्च के ऊपर स्थापित करना, नए बंपर का डिजाइन और बेहतर एयरोडायनामिक्स वाले नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

वाहन में वर्टिकल एलईडी हेडलैंप, एल-आकार की डे-टाइम रनिंग लाइट और वर्टिकल एलईडी टेललैंप पहले की तरह बरकरार रहने की संभावना है। केबिन में, किया साइरोस ईवी में दो 12.3 इंच की स्क्रीन, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इसमें व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) तकनीक भी दी जा सकती है, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी बिजली दी जा सकेगी। किया साइरोस ईवी में कंपनी अपने के1 प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रख सकती है, जिस पर आधारित अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स में 42 किलोवाट-घंटा और 49 किलोवाट-घंटा क्षमता वाले बैटरी पैक मिलते हैं। भारतीय मॉडल में भी इन्हीं विकल्पों के आने की संभावना है, साथ ही डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जो बैटरी को लगभग 30 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकेगा।

हीरो मोटोकॉर्प 5,02,890 इकाइयों की बिक्री के साथ पहले स्थान पर

नई दिल्ली। जून 2026 के बिक्री आंकड़ों में भारतीय दोपहिया वाहन बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

हालाँकि घरेलू बाजार में हीरो मोटोकॉर्प 5,02,890 इकाइयों की बिक्री के साथ पहले स्थान पर रही और होंडा 4,68,956 इकाइयों के साथ दूसरे स्थान पर, टीवीएस ने निर्यात में शानदार प्रदर्शन के दम पर कुल बिक्री का शीर्ष स्थान हासिल किया। टीवीएस मोटर ने कुल बिक्री के मामले में हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। टीवीएस की कुल बिक्री 5,65,417 इकाई तक पहुंच गई, जबकि हीरो मोटोकॉर्प 5,41,159 इकाइयों और होंडा 5,28,281 इकाइयों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। टीवीएस ने जून में 1,54,403 दोपहिया वाहनों का निर्यात किया, जो हीरो (38,269) और होंडा (59,325) के निर्यात आंकड़ों से काफी अधिक था। निर्यात में इस महत्वपूर्ण बढ़त ने टीवीएस को समग्र रूप से सबसे बड़ा विक्रेता बनने में मदद की। वार्षिक आधार पर, टीवीएस ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, उसकी कुल बिक्री में 47 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि होंडा की बिक्री 26 प्रतिशत बढ़ी।

इसके विपरीत, हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री में लगभग 2.3 प्रतिशत की हल्की गिरावट आई। घरेलू बाजार में हीरो मोटोकॉर्प की मजबूत पकड़ अब भी बनी हुई है, हालांकि उसकी बिक्री में मासिक और वार्षिक दोनों आधार पर कमी दर्ज की गई। वहीं, होंडा और टीवीएस दोनों ने घरेलू बाजार में भी सकारात्मक वृद्धि दिखाई। बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड ने भी जून 2026 में घरेलू बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें रॉयल एनफील्ड ने 1,02,930 मोटरसाइकिलों की बिक्री के साथ 33.75 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हासिल की।

अमेरिका-ईरान तनाव से सोने-चांदी के दाम में भारी गिरावट

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर सोने-चांदी के दामों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गुरुवार को वैश्विक कमोडिटी बाजार कॉमेक्स पर जहां बहुमूल्य धातुओं के दाम तेजी से खुले, वहीं बाद में उनमें तेज गिरावट दर्ज की गई। घरेलू मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने और चांदी की शुरूआत सुस्त रही और वे निचले स्तरों पर कारोबार करते दिखे। इससे पहले बुधवार को भी

इनके दामों में तेज गिरावट आई थी। घरेलू बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी के वायदा भाव में नरमी बनी हुई है। सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 1,43,451 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो बुधवार के 1,43,711 रुपए के बंद भाव से 260 रुपए कम था। खबर लिखे जाने तक यह 480 रुपए की गिरावट के साथ 1,43,231 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 2,22,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला, जो पिछले बंद भाव 2,23,437 रुपए से 1,437 रुपए कम था। खबर लिखे जाने तक यह 1,631 रुपए की गिरावट के साथ 2,21,806 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोने ने 1,80,779 रुपए और चांदी ने 4,20,048 रुपए के रिकॉर्ड स्तरों को छुआ था। मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव 4,087 .60 डॉलर प्रति औंस पर खुला, लेकिन खबर लिखे जाने तक यह 15 .10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,067 .50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। बुधवार को यह 4,082 .40 डॉलर पर बंद हुआ था और 4,075 डॉलर प्रति औंस के करीब फिसल गया था। वहीं, चांदी भी 58 .88 डॉलर पर खुलने के बाद 0 .45 डॉलर की गिरावट दर्ज करते हुए 58 .08 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। इस साल सोना 5,586 .20 डॉलर और चांदी 121 .79 डॉलर प्रति औंस के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे मौजूदा गिरावट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

आरबीआई के नए नियम से बैंकों को बड़ा झटका!

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए निर्देश के बाद बैंकों की कमाई पर असर पड़ सकता है। बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों के अनुसार, ग्राहकों को भेजे जाने वाले कुछ एसएमएस अलर्ट पर शुल्क वसूलने पर रोक लगने से बड़े बैंकों की सालाना फीस आय में करीब 300 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है। हालांकि, इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें ऐसे एसएमएस के लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा।

आरबीआई ने 24 जून को जारी अपने निर्देश में कहा था कि बैंक नियमों के पालन, जागरूकता और प्रचार से जुड़े एसएमएस अलर्ट के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं ले सकते। अब तक अधिकांश बैंक इन संदेशों की लागत निकालने के लिए ग्राहकों से हर तिमाही 15 से 18 रुपये तक स्नूस-शुल्क वसूलते थे। आरबीआई ने बैंकों को यह भी छूट दी है कि 500 रुपये या उससे कम के लेनदेन पर एसएमएस अलर्ट भेजना अब अनिवार्य नहीं रहेगा। यानी बैंक चाहें तो ऐसे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए स्नूस की जगह अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, बड़े निजी बैंक फिलहाल इस सुविधा को जारी रख सकते हैं। इन बैंकों का मानना है कि तुरंत एसएमएस अलर्ट ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाते हैं और धोखाधड़ी की आशंका कम करने में भी मददगार होते हैं।

रुपया शुरूआती कारोबार में चार पैसे टूटा

मुंबई। रुपया गुरुवार के कारोबारी दिन शुरूआती कारोबार में चार पैसे फिसलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 .52 पर आ गया। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव उत्पन्न होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से वैश्विक स्तर पर निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई और वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितताओं की आशंका बढ़ गई। हालांकि, घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख ने रुपये को समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95 .52 प्रति डॉलर पर खुला जो उसके पिछले बंद भाव से चार पैसे की गिरावट है।

भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार के कारोबारी दिन भू-राजनीतिक अनिश्चितता को धता बताते हुए मजबूत शुरूआत की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर निवेशकों की गहरी नजर होने के बावजूद, घरेलू निवेशकों ने बाजार में भरोसा जताया, जिससे प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में आई जबरदस्त खरीदारी ने बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुबह के शुरूआती कारोबार में निफ्टी 50 ने 111.35 अंकों की बढ़त के साथ 23,993.40 का स्तर छुआ, जो जल्द ही 24,000 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंच गया। वहीं बीएसई सेंसेक्स भी 342 अंक चढ़कर 76,845.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 50 पर इटरनल, टाइटन और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की। व्यापक बाजार में भी सकारात्मक रुख देखा गया, जहां

सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के करीब पहुंचा

निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 0.68 प्रतिशत और 0.41 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने सर्वाधिक बढ़त दर्ज की, जबकि निफ्टी आईटी इंडेक्स में मामूली कमजोरी रही। बाजार खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी से मिले मजबूत संकेतों ने भी घरेलू बाजार को सकारात्मक दिशा दी। वहीं भारतीय शेयर बाजार में बुधवार दोपहर के सत्र में भारी भूचाल आ गया, जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक दो प्रतिशत से अधिक टूट गए। दोपहर 2:20 बजे तक सेंसेक्स 1,784 अंक लुढ़ककर 76,396 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी 50 सूचकांक 541 अंक की गिरावट के साथ 23,900 के स्तर से नीचे चला गया। इस भारी गिरावट से महज कुछ ही घंटों के भीतर निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अधोसंरचनात्मक विकास और पुनर्वास कार्यों के लिये दी 2,300 करोड़ रुपए की स्वीकृति

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रुपए की मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास और पुनर्वास कार्यों को 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव अनुसार राज्य डाटा सेंटर के आधुनिकीकरण, आई.टी एवं डिजास्टर रिकवरी सहित अन्य कार्यों के लिए मंत्रि-परिषद ने 800 करोड़ की मंजूरी दी है। विभाग के ही तीन अन्य प्रस्तावों पर विज्ञान पार्क- एकल नागरिक डाटाबेस परियोजना और बॉयो टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना एवं संचालन के लिए वर्ष 2031 तक निरंतरता के लिए 123 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक और प्रस्ताव अनुसार ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वामित्व योजना के निष्पादित हस्तांतरण अभिलेखों पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक :2026 को भी मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव अनुसार मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसी तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूँ, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति : 2026 को भी मंत्रि-परिषद ने स्वीकृति दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश के 65 नगरीय निकायों और उनके आस-पास के वन क्षेत्रों में नगरीय वन विकसित करने के लिए नमो हरित नगर योजना को 100 करोड़ की स्वीकृति दी है। जल संसाधन विभाग द्वारा पृथक-पृथक 3 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और पुन: विस्थापन के लिए 3 प्रस्ताव अनुसार मंत्रि-परिषद ने पन्ना जिले की केन-बेतवा लिंक परियोजना, रूंज सिंचाई परियोजना और मझगांव सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए अतिरिक्त रूप से 202 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राजपत्रित सेवा भर्ती नियम : 2022 के तहत भर्ती प्रक्रिया को स्वीकृति दी। इसी तरह मंत्रि-परिषद द्वारा लीगल और डिफेंस काउंसिल सिस्टम योजना की वर्ष 2031 तक निरंतरता के लिए 42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वित्त विभाग के प्रस्ताव अनुसार विभिन्न लिखतों पर देय उपकार में छूट देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने शिक्षा विभाग की लोक-वित्त पोषित कार्यक्रमों योजनाओं एवं परियोजनाओं के परिक्षण की योजना को 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 543 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

मंत्रि-परिषद ने एमपीएसईडीसी द्वारा संचालित एवं संग्रहीत म.प्र. स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार म.प्र. स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, आईटी एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन-आईटी अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना अंतर्गत सरकार की सेवाओं को संगठित करने व दक्ष इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान करने के लिए भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12 दिसंबर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित है। परियोजना अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आई.टी. एप्लीकेशन्स के लिए होस्टिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। स्टेट डाटा सेंटर ई-गवर्नेंस क्षेत्र की बहु-उपयोगी एवं डिजिटल भारत की अवधारणा को साकार करने हेतु डिजीटल मध्यप्रदेश के लिये अति आवश्यक अधोसंरचना है। उक्त अधोसंरचना पूर्णत: सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी आधारित है, जो 365 दिन 24 घंटे निरंतर संचालित रहती है। स्टेट डाटा सेंटर के माध्यम से ही प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली नागरिक सेवाओं को नागरिकों को उनके निकटतम स्थल पर सुगमता पूर्वक ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है।

बदलते तकनीकी परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्प्यूटिंग आदि इमर्जिंग फ्रंटियर टेनोलॉजीज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी नवीन अधोसंरचना स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, जो राज्य शासन को नागरिक सेवाओं को अधिक दक्षतापूर्वक प्रदान करने हेतु इन तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाए। अधोसंरचना में वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति, कूलिंग अधोसंरचना आदि संबंधित नॉन-आईटी अधोसंरचना के संवर्द्धन की आवश्यकता भी होगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में डाटा सेंटर के विस्तार के लिए एसडीसी 3.0 परियोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। एमपीएसडीसी 3.0 डाटा सेंटर एक्पैंशन परियोजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा। प्रत्येक चरण के अंतर्गत डेटा सेंटर के विभिन्न घटकों का क्रमिक विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। पहले चरण में डाटा सेंटर साइट के लिए कोर नॉन आईटी एवं आईटी इंफ्रॉस्ट्रक्चर, कंप्यूटर स्टोरेज और नेटवर्क, दूसरे चरण में डीआर साइट का निर्माण एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण और तीसरे चरण में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। यह स्वीकृति राज्य में बढ़ती डिजिटल सेवाओं, डेटा प्रोसेसिंग मांग एवं भविष्य की उन्नत तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है, जिससे एक स्केलेबल, सुरक्षित एवं उच्च दक्षता युक्त डेटा सेंटर वातावरण का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रि-परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत विज्ञान पार्क, एकल नागरिक डाटाबेस परियोजना और बॉयो टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना एवं आगामी 5 वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए संचालन की निरंतरता के लिए 123 करोड़ की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार विज्ञान पार्क की स्थापना संबंधी योजना के लिए 39 करोड़ 39 लाख रुपए, एकल नागरिकता डाटाबेस के लिए 75 करोड़ और बॉयो टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना और संचालन संबंधी योजनाओं के लिए 8 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। उज्जैन स्थित आचार्य वराह मिहिर न्यास परिसर में अत्याधुनिक तारामंडल एवं खगोलीय वेधशाला स्थापित की जा रही है। इसमें 1 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप एवं 4.5 मीटर रेडियो टेलीस्कोप जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं एवं युवाओं को उच्चस्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान के अवसर प्राप्त होंगे। विज्ञान पार्क संबंधी योजना खगोल विज्ञान के अध्ययन, अनुसंधान एवं जन-जागरुकता को बढ़ावा देने के साथ समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा अंधविश्वासों के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, यह उज्जैन को राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख खगोलीय अनुसंधान एवं विज्ञान प्रसार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। समय एकल नागरिक डाटाबेस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों का एकीकृत डेटाबेस विकसित किया जा रहा है, जिससे शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

परियोजना से नागरिकों की मूलभूत जानकारी का एकल एवं समेकित स्रोत उपलब्ध होगा, जिससे विभागीय स्तर पर पृथक-पृथक पंजीयन की आवश्यकता कम होगी तथा सेवाओं का प्रदाय अधिक सरल, समयबद्ध एवं नागरिक-केंद्रित बन सकेगा। डेटाबेस में उपलब्ध प्रमाणित जानकारी के आधार पर विभिन्न सेवाएँ एवं योजनाओं का लाभ नागरिकों को "सिंगल क्लिक" पर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। एस.सी.डी परियोजना के साथ-साथ "परिचय" परियोजना के माध्यम से आधार आधारित ऑथेंटिकेशन एवं ई-केवाईसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे डी.बी.टी प्रक्रियाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। दोनों परियोजनाएँ डेटा समेकन, आधार प्रमाणीकरण एवं विभागीय डेटा साझाकरण के माध्यम से राज्य की ई-गवर्नेंस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं तथा भविष्य की डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली एवं विजन@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। मध्यप्रदेश बॉयो टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना तथा संचालन से संबंधित योजना का उद्देश्य प्रदेश में बॉयो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की नेशनल बॉयो टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम के अंतर्गत संचालित इस योजना के तहत स्टार्ट-अप, नवोन्मेषकों तथा सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमियों को इन्क्यूबेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

मंत्रि-परिषद ने शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं एवं बालक को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-2031 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश मे स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाने वाली बालिका एंव बालक को मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना के अन्तर्गत लाभांवित किया जाएगा। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय किये जाने के लिए संचालित योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता के लिए राशि 495 करोड रुपए पर मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूँ, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति : 2026 को स्वीकृति

भारत सरकार द्वारा राज्य में गेहूँ, धान (चावल), ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है। विक्रय कार्य व्यवस्थित रूप से किये जाने एवं उपज का अधिकतम मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश उपार्जित खाद्यान्न (गेहूँ, धान, ज्वार एवं बाजरा) निस्तारण नीति 2026 को मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है। नीति अनुसार एक राज्य स्तरीय कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी। समिति द्वारा उपज के मात्रा निर्धारण के बाद प्रस्तावित उक्त मात्रा विक्रय करने के पूर्व रिजर्व प्राईज अपसेट मूल्य तय करना एवं ई-निविदा/ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से दरें आमंत्रित करना, प्राप्त दरों का परीक्षण के बाद अनुमोदन तथा निस्तारण की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश आईटी, आईटीइएस एंड ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आईटी, आईटीइएस एंड ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी : 2023 के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नीति की कंडिका 15, 12.6 और 12.11 में नए प्रावधान प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नीति को निवेश प्रोत्साहन विभाग की मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी अनुरूप बनाकर ईएसडीएम इकाइयों के लिए अधिक आकर्षक एवं अनुकूल बनायी गई है। ताकि इस नीति के तहत निवेशकर्ता एवं प्रदेश को लाभ प्राप्त हो सके। स्वीकृति अनुसार, अगर कोई पुरानी आईटी या डेटा सेंटर कंपनी अपना काम बढ़ाना चाहती है, तो उसे अपने मौजूदा निवेश में कम से कम 30% और पैसा लगाना होगा या अपनी जगह का एरिया 30% बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली (ईएसडीएम) कंपनियों को अपनी मशीनों में कम से कम 30% (न्यूनतम 15 करोड़ रुपए) या 50 करोड़ रुपए (जो भी कम हो) का नया निवेश करना होगा और उत्पादन क्षमता 20% बढ़ानी होगी। ऐसा करने पर इन सभी कंपनियों को नई कंपनी की तरह ही सरकारी मदद मिलेगी।

पीथमपुर प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केन्द्रः मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। ह्लमध्यप्रदेश सरकार उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। हमारी प्राथमिकता है कि उद्योगों से युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो और प्रदेश आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में आधुनिक पाइप, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नई इकाई कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की चौथी नवीन विनिर्माण इकाई के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने फैक्ट्री परिसर में शिव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उद्योगों का विस्तार केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास का भी आधार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई विनिर्माण इकाई के प्रारंभ होने से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश में कृषि और जल प्रबंधन से जुड़े आधुनिक उत्पादों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योग, कृषि और तकनीक के समन्वय से विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन इकाई का अवलोकन किया और पाइप निर्माण में उपयोग की जा रही अत्याधुनिक मशीनों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कंपनी द्वारा कृषि, सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कंपनी प्रबंधन को बधाई दी।

कंपनी के एमडी श्री कुणाल अग्रवाल ने जानकारी दी कि किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना लगभग 40 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में कंपनी की कुल 5 इकाइयां संचालित हैं, जिनमें से 4 इकाइयां पीथमपुर में स्थित हैं। कंपनी पीवीसी पाइप्स, एचडीपीई पाइप्स, सीपीवीसी एवं यूपीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स के निर्माण के साथ-साथ वॉटर टैंक, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के निर्माण का कार्य करती है। चौथी नवीन इकाई में एचडीपीवी और डीडब्ल्यूसी पाइप्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे कृषि, सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आधुनिक उत्पाद उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बनाया परियोजना को विवाद रहित

उच्च स्तरीय बैठक से संभव हुआ चार राज्यों को लाभः जल संसाधन मंत्री

भोपाल। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दे को सुलझाते हुए परियोजना को विवाद रहित बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर चार राज्यों मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने मिलकर सरदार सरोवर परियोजना के 30 लंबित मुद्दों का समाधान किया है। प्रधानमंत्री जी राज्यों के बीच परस्पर प्रगाढ़ संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में नर्मदा परियोजनाओं से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश के हित के सभी मुद्दों पर सतत रूप से सजग और प्रयासरत रहते हैं। उच्च स्तरीय बैठक में इस तरह समाधान निकाला गया है कि सभी राज्यों को लाभ हुआ है। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटील उपस्थित थे।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नर्मदा परियोजनाओं के संबंध में कई वर्षों से चारों राज्य अलग-अलग प्रकार से गणना कर राशियों की मांग कर रहे थे। फरवरी 2026 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में अपना अभिमत दिया था। इस अभिमत के अनुसार मध्य प्रदेश को डेढ़ हजार करोड़ रुपए गुजरात राज्य को भुगतान करने की स्थिति बन रही थी, क्योंकि इसमें गुजरात राज्य पर 50 प्रतिशत के व्यय की हिस्सेदारी दी गई थी। गृह मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में चारों राज्यों के साथ बैठकर हुए गंभीर विचार-विमर्श गुजरात राज्य को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत व्यय वहन करने का निर्णय लिया गया।

श्री सिलावट ने कहा कि इस निर्णय के कारण मध्यप्रदेश की देनदारी 1,500 करोड़ से कम होकर मात्र 231 करोड़ रह गई है। यह परियोजना अब पूरी तरह विवाद रहित हो गई। मध्यप्रदेश को 31 लाख हेक्टयर में सिंचाई और 85 पैसे प्रति यूनिट के मान से बिजली निरंतर मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश अनेक क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर है। श्री सिलावट ने मध्यप्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया।

लोक कलाओं में शुरू करें सर्टिफिकेट कोर्स : राज्य मंत्री

भोपाल। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने मंत्रालय में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोक कलाओं से संबंधित नए सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश की स्थिति, विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के प्रयासों, अधोसंरचना विकास और विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन स्तर पर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाए और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में कुल 122 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें संगीत के 48, नृत्य के 30, ललित कला, नाट्य एवं रंगकर्म के 08 तथा अन्य 06 पाठ्यक्रम शामिल हैं। राज्य मंत्री श्री लोधी ने इन पाठ्यक्रमों की सराहना की और जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों तथा उनके अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों और कोर्सेस का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि दूर-दराज के विद्यार्थियों तक भी इसकी जानकारी पहुँच सके।

मध्यप्रदेश पुलिस को मिले 436 नए उप निरीक्षक एवं सूबेदार

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उप निरीक्षक एवं सूबेदारभर्ती परीक्षा-2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश पुलिस को 8 वर्षो के लंबे अंतराल के बाद सूबेदार एवं उपनिरीक्षक संवर्ग के 436 पुलिस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। इस भर्ती के माध्यम से पुलिस विभाग को युवा, प्रशिक्षित एवं ऊजार्वान अधिकारियों का नया नेतृत्व प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा जनसेवा की क्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के पालन में पुलिस विभाग में अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी क्रम में आरक्षक भर्ती वर्ष-2025 के अंतर्गत विज्ञापित 7,500 रिक्त पदों पर न्यायालय के आदेश के पालन में 87 प्रतिशत पदों का परीक्षा परिणाम जारी कर 6,520 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर आधारभूत प्रशिक्षण हेतु भेजा जा चुका है।

इसी श्रृंखला में सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष-2025 के अंतर्गत 500 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से तीन चरणों में संपन्न कराई गई। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 16 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ किया गया, जबकि मुख्य परीक्षा 29 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई। मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल 1,639 अभ्यर्थियों (473 महिला एवं 1,166 पुरुष) का चयन अगले चरण के लिए किया गया। इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक प्रवीणता परीक्षा (ढएळ), शारीरिक माप परीक्षण (ढटळ), दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा 05 जून से 11 जून 2026 तक भोपाल एवं जबलपुर में निर्धारित मानकों, पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 07 जुलाई 2026 को अंतिम परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया गया। न्यायालय के आदेश के पालन में 13 प्रतिशत पदों को रोके रखते हुए 87 प्रतिशत पदों का परिणाम जारी किया गया, जिसमें कुल 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 313 पुरुष एवं 123 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के लिए निर्धारित 35 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित सभी 123 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पुलिस में लगातार आयोजित की जा रही भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। महिला अधिकारियों की बढ़ती संख्या पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मध्यप्रदेश बना वक्फ बोर्ड का पुर्नगठन करने वाला पहला राज्य

तीस वर्षों से लंबित सरदार सरोवर परियोजना का सर्वसम्मति से समाधान होना बड़ी उपलब्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से विगत 30 वर्षों से सरदार सरोवर परियोजना को लेकर लंबित जटिल मुद्दे का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह विषय मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच लंबित था। भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा फरवरी 2026 में अभिमत दिया कि पुनर्वास की लागत भागीदार राज्यों के मध्य विभाजित होनी चाहिए। अभिमत के अनुसार मध्यप्रदेश को लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने की स्थिति बन रही थी। नई दिल्ली में हुई बैठक में तय किया गया कि 50% के स्थान पर 75% का खर्चा गुजरात द्वारा ही दिया जाए, और इस प्रकार मध्यप्रदेश को अब केवल रुपए 217 करोड़ की राशि देना होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में में नये अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का गठन कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड का पुर्नगठन करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रही ज्ञान भारतम्योजना में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। अब तक 34 लाख 45 हजार से अधिक पांडुलिपि पन्नों का पंजीकरण और 12 लाख से अधिक का सत्यापन किया जा चुका है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा 'जम्बू द्वीप का नक्शा, पन्ना से 'रसिक प्रिया', बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित 'श्रीमद्भागवत' और दतिया से ऐतिहासिक ताम्रपत्र जैसी अमूल्य धरोहरें प्राप्त हुई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्यप्रदेश ने नया इतिहास रचा है। प्रदेश में गत तीन वर्षों में 15 हजार 819 करोड़ रुपए लागत के 5 लाख 20 हजार 400 से अधिक कार्य हुए हैं। वर्ष 2024 में 1 हजार 367 करोड़ रुपए लागत से 60 हजार 428 कार्य कराए गए। वर्ष 2025 में 4 हजार करोड़ रुपए लागत के 1 लाख से अधिक कार्य सम्पन्न हुए। वर्ष 2026 में 10 हजार 452 करोड़ रुपए लागत के 3 लाख 60 हजार, कार्य प्रदेश में सम्पन्न हुए। वर्ष 2026 में जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रथम 5 जिले बड़वानी, खण्डवा, नीमच, उज्जैन और खरगोन रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश को खेलों में बड़ी सफलता मिली है। जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी एशिया कप-2026 टूनार्मेंट में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। भारतीय बालक एवं बालिका हॉकी टीम में प्रदेश के कुल 10 खिलाड़ी शामिल रहे। ये खिलाड़ी भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सिवनी और बड़वानी जिले के साधारण परिवारों से हैं। राज्य सरकार ने हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को 3 लाख रूपए प्रति खिलाड़ी और कांस्य पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को एक लाख रूपए प्रति खिलाड़ी प्रोत्साहत राशि प्रदान की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब मध्यप्रदेश की धरती पर रक्षा उपकरण, मिसाइल और हथियार भी बनेंगे। शिवपुरी जिले के पाली में 103 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये की अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट का शिलान्यास हुआ है। यहाँ हथियारों में प्रयुक्त होने वाले सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस प्रोपेलेन्ट का निर्माण होगा। चंबल क्षेत्र के 10 हजार से भी अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि भोपाल के कोलार रोड क्षेत्र में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, सतगढ़ी का गत दिवस भूमि-पूजन किया गया। यह पुनीत कार्य भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सम्पन्न हुआ। सतगढ़ी पार्क 150 करोड़ रुपए की लागत से 70 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। इससे 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सतगढ़ी में 25 एकड़ में 10 हजार क्षमता का कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर भी बनेगा। यह परियोजना 'वर्क-लिव-ग्रो' मॉडल पर आधारित है। इसमें गारमेंट, टॉयज, आईटी, एआई, लॉजिस्टिक्स आदि से जुड़े उद्योगों को स्थापित किया जाएगा।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।